● वर्ष-4
● अंक-58
रायपुर, बुधवार
16 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6»»» क्या है बच्चों की मालिश का...

महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा

महाराष्ट्र में 20 नवंबर, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर होगी वोटो की गिनती

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र के लिए विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान किया। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। चुनावी तारीख को का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि 23 नवंबर को वोटो की गिनती होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी तथा नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर होगी। कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र चार नवंबर, 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या

महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 9.63 करोड़ हैं, जिसमें 4.97 करोड़ पुरुष मतदाताओं की संख्या है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 4.66 करोड़ है। अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1.85 करोड़ है। जबकि पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 20.93 लाख है।

महाराष्ट्र में कुल 52 हजार 789 जगहों पर एक लाख 186 पोलिंग स्टेशन होंगे। इसमें शहरी इलाकों में 42 हजार 604 और ग्रामीण इलाकों में 57 हजार 582 हैं। वहीं एक पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 960 मतदाताओं के वोट डालने का एवरेज हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, मतदान के दौरान कतारों के बीच में थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाई जाएंगी ताकि अपनी बारी का इंतजार कर रहे मतदाता थोड़ी-थोड़ी देर में बैठ सकें। ये व्यवस्था हर मतदान केंद्र पर मिलेगी।

महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी गणित

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट की कुल 288 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महा विकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। 2019 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी। तब बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के लिए 124 सीटें छोड़ी थी। वहीं एनडीए ने अपने अन्य सहयोगियों के लिए 12 सीटें छोड़ रखी थीं। इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 और 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी।

लोकसभा चुनाव में क्या रहा गठबंधन का प्रदर्शन

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। जिसमें तीनों दलों ने मिलकर मात्र 17 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि महा विकास अघाड़ी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक बढ़िया रहा था। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस शामिल हैं, ने शानदार प्रदर्शन किया और 48 में से 30 सीटें जीतीं।

झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्तूबर को

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्तूबर को जारी होगी। जबकि नामांकन 25 अक्तूबर से शुरू होंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्तूबर को होगी। नाम वापसी 30 अक्तूबर को होगी। जबकि मतदान 13 नवंबर को होगा।

वहीं दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 22 अक्तूबर को जारी होगी। नामांकन 29 अक्तूबर से होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्तूबर को होगी। जबकि नाम वापसी एक नवंबर को होगी। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि झारखंड में कुल मतदाता 2.06 करोड़ हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 1.31 करोड़ और महिला मतदाता 1.29 करोड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में कुल 29562 मतदान केंद्र होंगे। इसमें 20221 लोकेशन पर मतदान केंद्र हैं। इसमें 5042 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र और 24520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। आयोग के मुताबिक हर मतदान केंद्र पर औसत 881 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों में से सामान्य सीटें 44, एसटी सीटें 28 और एससी नौ हैं। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है।

आरोपों का चुनाव आयोग ने किया खंडन

हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर लगाए गए आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर बार चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर नए-नए आरोप सामने आते हैं। इस बार भी बैटरी को लेकर आरोप लगाया गया। अगली बार कुछ और आएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि ईवीएम की बैटरी एक कैलकुलेटर की तरह होती है और इसमें तीन स्तरीय सुरक्षा होती है।

कुमार ने कहा कि पेजर की तरह ईवीएम में हेराफेरी करना असंभव है और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के अगले बड़े आरोप का इंतजार कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि ईवीएम बैटरी के बारे में मुद्दा नया है, लेकिन ईवीएम में बैटरी सहित तीन स्तरीय सुरक्षा होती है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने पहले ही बड़ी संख्या में भाग लेकर मतदान प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त किया है। यह प्रतिक्रिया विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस द्वारा एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ पर चिंता जताए जाने के बाद आई है।

झारखंड चुनाव पर भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक

अगले महीने होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की मंगलवार शाम यहां बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष सीईसी सदस्यों में शामिल हुए। बैठक में संभावित उम्मीदवारों की सूची पर विचार-विमर्श किया।

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के लिए भाजपा की प्रभारी अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ के अलावा पार्टी की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी बैठक में भाग लिया।

झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार खड़े कर सकती है। वहीं, 14 सीटें गठबंधन में शामिल पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है।

वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को प्रत्याशी बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रियंका को प्रत्याशी बनाए जाने का एलान किया।

बता दें कि प्रियंका खुद भी वायनाड से पार्टी का प्रतिनिधित्व करने को लेकर हामी भर चुकी हैं। विगत जून महीने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे की घोषणा के बाद प्रियंका ने कहा था कि यहां से चुनाव लड़ना उनका सौभाग्य होगा। वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थीं। उसके बाद से वह पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी वाली सूची जारी की।

रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि उप-निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी 25 अक्टूबर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग 28 अक्टूबर को की जाएगी। **(विस्तृत समाचार पेज 8 पर)**

हरियाणा का मुख्यमंत्री आज तय होगा

पंचकूला में विधायकों की बैठक

चंडीगढ़। हरियाणा की नई सरकार के गठन की तैयारियां बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक से शुरू हो जाएगी। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में पार्टी के विधायक पंचकूला स्थित पार्टी दफ्तर में अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसी बैठक में तय होगा कि हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बैठक में नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज में से किसी एक के नाम पर मुहर लगेगी। भाजपा ने अपने सभी 48 विधायकों को अगले दो दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश जारी किए हैं। विधायक दल का नेता चुनने से पहले सभी विधायक शाह और यादव के साथ ब्रेक फास्ट करेंगे। उसके बाद विधायक दल के नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इसलिए आना पड़ा अमित शाह को

बीते मार्च में मनोहर लाल को हटाकर विधायक दल की बैठक में जब नायब सिंह सैनी का नाम रखा गया तो अनिल विज नाराज हो गए थे। वह बैठक से बाहर निकल गए थे। चुनाव से पहले अनिल विज मुख्यमंत्री की दावेदारी जता चुके हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी समय-समय पर दावेदारी जताते रहे हैं। लिहाजा इस तरह के विवादों से बचने के लिए शाह को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले 2022 में शाह यूपी में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे और योगी के नाम पर मुहर लगाई गई थी।

शाह ने किया था नायब सिंह सैनी के नाम का एलान

भाजपा नेताओं ने बताया, विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक की ओर से पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक को प्रस्तावक नियुक्त किया जाएगा। प्रस्तावक बैठक में नायब सिंह सैनी का नाम रखेंगे और सर्वसम्मति से सभी विधायक उनके नाम पर मुहर लगा देंगे। प्रस्तावक का नाम बैठक से पहले तय किया जाएगा। आमतौर पर पार्टी के वरिष्ठ विधायक को ही प्रस्तावक बनाया जाता है। हालांकि नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर कोई किंतु-परंतु नहीं है। भाजपा ने उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यहां तक कि अमित शाह ने चुनाव से पहले पंचकूला में कार्यकर्ताओं की बैठक एलान कर दिया था कि भाजपा की सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में नायब सिंह सैनी को ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते आए हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में नायब सिंह सैनी का कद भी बढ़ा है। ऐसे में उनके नाम को लेकर कोई संशय नहीं है। विधायक दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।

प्रमुख समाचार

महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी बसपा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी राज्य चुनावों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि मायावती की पार्टी अब किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। महाराष्ट्र व झारखण्ड में चुनावी तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए मायावती ने एक्स पर लिखा कि चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक-साफ अर्थात् धनबल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। इसके साथ ही यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर-उधर न भटकें बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान कारवाँ के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। इसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव की टेंशन उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी।

आदर्श आचार संहिता से चंद मिनट पहले दिवाली बोनस

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा एलान किया। उन्होंने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की। शिंदे ने कहा कि बीएमसी (बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन) कर्मचारियों को भी 29 हजार रुपये बोनस मिलेगा। खास बात यह है कि इस साल राशि पिछली बार हुई घोषणा की तुलना में तीन हजार रुपये ज्यादा है। सरकार ने यह भी कहा है कि किंडरगार्टन कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों और आशा वर्कर्स को भी बोनस का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का एलान भी कर चुकी है। सरकार की आज की घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब किसी भी तरह के सरकारी लाभ वाले एलान पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद सरकार पैसे जारी कर सकती है। इससे पहले बीते 11 अक्तूबर को राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का एलान किया।

पूर्व सीजे रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर नोकझोंक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर न्यायाधीशों और एक याचिकाकर्ता के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुरक्षा बुलाई और वादी को अदालत कक्ष से बाहर निकालने को कहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने की, जिन्होंने अंततः अरुण रामचंद्र हुबलीकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने हुबलीकर द्वारा बार-बार दायर किए गए आवेदनों पर निराशा जताई। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। पेशे से वकील हुबलीकर ने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच का आह्वान किया। इसमें पूर्व सीजेआई पर हुबलीकर की अवैध समाप्ति से संबंधित फैसले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति गोगोई के कार्यों ने उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हुबलीकर ने अदालत के समक्ष कहा कि जस्टिस गोगोई ने एक फैसले में अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया.

अपनी गाड़ी या नेमप्लेट पर कुछ लिखने पर तगड़ा जुर्माना

नई दिल्ली। नए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, और इनमें वाहनों पर अनुचित शब्द, नारे लिखने या प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए जुर्माना शामिल है। चाहे वह कोई कोट (उद्धरण) हो, जाति-संबंधी वाक्यांश हों या सजावटी नेमप्लेट (नामपट्टिकाएं) हों। आपको ये ट्रेंडी और बिना कोई नुकसान वाला लग सकता हैं। लेकिन अब इनके नतीजे के रूप में आप दंड के भागी बन सकते हैं। यहां आपको भारत में इन ट्रैफिक नियमों के बारे में बता रहे हैं। वाहनों के पीछे व्यक्तिगत उद्धरण, कविताएं, नारे या यहां तक कि जाति-संबंधी वाक्यांश लिखना एक आम बात हो गई है। कुछ वाहन मालिक अपनी नंबर प्लेट को कस्टमाइज कराते हैं, इतना ही नहीं वे इसमें नाम या प्रतीक तक जोड़ देते हैं। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम के तहत, इसे अवैध माना जाता है। इन कानूनों से अनजान होने की बात कह कर बच नहीं सकते हैं। और आपको इन तथाकथित हानिरहित कस्टमाइजेशन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, अपनी कार, बाइक या यहां तक कि व्यावसायिक वाहनों पर कुछ भी अनुचित लिखना कानून का सीधा उल्लंघन है।

एयर इंडिया के 22 विमानों में बम की धमकी, फ्लाइट मोड़ी

नई दिल्ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये मंगलवार को 22 विमानों में बम की धमकी दी गई। इसमें एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जा रही फ्लाइट में बम होने की बात कही गई। इसके बाद फ्लाइट को कनाडा की ओर मोड़ दिया गया। जहां फ्लाइट की जांच की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सभी धमकियां फर्जी निकलीं। एक्स के जरिये एक पोस्ट में पांच घंटे में 22 अलग-अलग फ्लाइटों में बम की धमकी दी गई। इसके बाद यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ में हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर-बंगलूरू वाया अयोध्या फ्लाइट (IX765) में बम की धमकी दी गई। इस विमान को अयोध्या में उतारा गया और जांच की गई। इसके अलावा स्पाइसजेट के दरभंगा-मुंबई विमान (SG116) और अकासा के सिलीगुड़ी-बंगलूरू विमान (QP 1373) में भी बम होने की धमकी मिली। सूचना मिलने तक यह दोनों विमान लैंड कर चुके थे। एयरपोर्ट पर दोनों विमानों की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बल ने जांच की।

भारत को सेंटर में रखकर ही अमेरिका में हो रहा इस बार चुनाव!

अभिनय आकाश

भारत में लोकसभा चुनाव के बाद हुए दो राज्य के विधानसभा परिणामों के बाद सरकार बनाने की कवायद और विपक्ष का ईवीएम व चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने का काम चल रहा है। वहीं अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करीब आ रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। अमेरिकी चुनाव और संसदीय सिस्टम में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो भारत में लोगों को हैरान कर देंगे। सबसे मजेदार है वहां कि संसद के दोनों सदनों के चुनाव के सिस्टम और अपने देश की संसद के दोनों सदनों के चुनाव सिस्टम में अंतर। वहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी हमारे सिस्टम से काफी अलग होता है। भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रही है। 5 नवंबर को अमेरिका में वोटिंग होनी है। इससे पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अपना हर दांव आजमाने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिकी चुनाव में इस बार भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में नजर आ रहा है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव सरीखे मुद्दे का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लाइमलाइट में आना। ऐसा लग रहा मानो अमेरिकी चुनाव में जो मुद्दे सुनाई पड़ रहे हैं जो जाने-पहचाने से हैं।

रिपब्लिकन कैडिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती तो किसी से छिपी नहीं है। आपको टेक्सास के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम तो याद ही होगा। जब मोदी ने ट्रम्प की मौजूदगी में अबकी बार ट्रम्प सरकार का नारा दिया था। अमेरिका में एक साल बाद ही चुनाव थे। ऐसे में मोदी के इस बयान को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए विरोध और ट्रम्प के समर्थन में देखा गया। हालांकि उस चुनाव में ट्रंप की जीत नहीं हो पाई थी। 24 फरवरी, 2020 को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भी

आयोजन किया गया था। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को मात देने के लिए पूरे जी जान से लगे हैं। इस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बार बार तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप ने इस इंटरव्यू में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि मोदी न सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं बल्कि बेहद अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी के लिए लोगों की दीवानगी का जिक्र किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम मोदी के अंदाज में बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद से निपटने की तैयारी कैसे की थी।

ट्रंप ने कहा कि मोदी के आने से पहले भारत में हर साल उन्हें (पीएम) बदला जाता था। वहां बहुत ज्यादा अस्थिरता थी। इसके बाद वह आए। वह महान हैं। वह मेरे मित्र हैं। बाहर से वह ऐसे दिखते हैं, जैसे वह आपके पिता हैं। वह सबसे अच्छे हैं। हाउडी मोदी की सफलता के बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेडियम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग पागल हो रहे थे और हम घूम रहे थे..हम बीच में चल रहे थे, हर किसी को हाथ हिला रहे थे। हमारे सामने कुछ ऐसे मौके आए, जब कोई भारत को धमका रहा था। मैंने कहा कि मुझे मदद करने दीजिए। मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता हूं। इस पर मोदी ने कहा-यह मैं करूंगा। जो भी जरूरी होगा, वह मैं करूंगा। ट्रंप ने अपने 88 मिनट लंबे साक्षात्कार में लगभग 37 मिनट तक मोदी के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की।

टेस्ला और स्पेसएक्स बॉस ने पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन ट्रम्प के संभावित रूप से चुनाव हारने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ट्रम्प हार जाते हैं, तो मैं निराश हो जाऊंगा। मस्क का साक्षात्कार पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रम्प के साथ दिखाई देने के कुछ दिनों बाद आया है। पेंसिल्वेनिया की रैली में उन्हें पूर्व राष्ट्रपति के प्रति अपना मजबूत समर्थन दिखाते हुए डांस भी किया था। एलन मस्क ने ट्रंप के लिए वोट करने की अपील करते हुए लोगों से कहा है कि अगर ट्रंप इस बार चुनाव नहीं जीते तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा।

एलन मस्क ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक प्रशासन अगले चार वर्षों तक के लिए फिर से सत्ता में आते हैं तो वे इतने सारे अवैध को वैध कर देंगे कि अगले चुनाव में कोई भी स्विंग स्टेट नहीं होगा और यह एक एकल-दलीय देश होगा। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी का बोलबाला है, यहां के सभी सरकारी दफ्तरों, इलेक्टोरल वोट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी का ही दबदबा हैष यहां तक कि राज्य के विधानमंडल और कांग्रेस डेलीगेशन में भी डेमोक्रेट्स सुपर मेजोरिटी में हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला फेमस डॉयलाग तो सभी को याद होगा। जिसमें वो बीजेपी को नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी, लोगों को एक दूसरे से लड़वाने और धर्म के आधार पर बांटने वाली विभाजनकारी ताकत के रूप में उल्लेखित करते नजर आते हैं। उसी तर्ज पर एलन मस्क ने अपने एक पोस्ट में कहा था कि अतीत में मैंने डेमोक्रेट को वोट दिया था, क्योंकि वे (ज्यादातर) दयालु पार्टी थे।

स्कूल भवन का हुआ टेंडर, पुराना भवन तोड़ने के बाद टेंडर निरस्त, पालकों और शिक्षकों ने लगाया ताला

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम पीपरछेड़ी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मंगलवार को पालकों व बच्चों ने स्कूल में ताला लगा दिया है और आज स्कूल बंद है और बच्चे स्कूल के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बच्चे लंबे समय से एक शिक्षक की मांग कर रहे हैं और शिक्षकों की मांग पूरी न होने के कारण आज सभी ने एक साथ मिलकर फैसला लिया और स्कूल में ताला लगा दिया गया है वही सामने बैठकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसंत बाग मौके पर पहुंचे हुए हैं परंतु बच्चे उनकी एक नहीं सुन रहे अभी तक विद्यालय में ताला लगा हुआ है बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, सभी कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

गांव के वरिष्ठ नागरिक कृष्णा राम साहू ने बताया कि हम लोग लंबे समय से प्रमुख विषयों के शिक्षकों की मांग कर रहे थे परंतु प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने अब तक किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए मजबूरी बस हमें इस तरह का कदम उठाना पड़ा और आज विद्यालय में छुट्टी नहीं बल्कि हड़ताल है यहां पर बच्चे विद्यालय के सामने शिक्षकों की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और अधिकारी तो पहुंचे हैं परंतु उनके द्वारा किसी तरह का संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा है बालकों में यह आक्रोश लंबे समय से पनप रहा था क्योंकि उनके बच्चे जो की शासकीय स्कूलों पर भरोसा करके जाते हैं उन्हें

बेहतर शिक्षा शिक्षकों के अभाव में नहीं मिल पा रही थी।

गांव के उपसरपंच खेमराज गोस्वामी ने बताया कि भवन निर्माण की समस्या है पहले स्वीकृत हो गया है करके भवन को तोड़ दिया गया है लेकिन अब नए भवन के निर्माण को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसे लेकर उन्होंने हड़ताल स्थल पर आए एसडीएम प्रतिमा ठाकरे सहित शिक्षक अधिकारी के समक्ष रखी, उन्होंने बताया कि 34 साल से यहां हाइ स्कूल बना है लेकिन अब तक यहां पर भवन नहीं बन पाया है लगातार मांग कर रहे चंदे से भवन बनाया था उसे नए भवन की स्वीकृति और टेंडर जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुआ था उसे भाजपा सरकार में कैंसिल कर दिया गया।

जब उपसरपंच अपनी बातों को रख रहे थे तो एसडीएम ने उपसरपंच को उसकी राजनैतिक पार्टी के बारे में पूछ लिया जिसपर सभी नाराज़ हुए हम यहां अपनी समस्या को लेकर हैं किसी राजनीति के लिए नहीं वहीं जब शिक्षकों को जानकारी पूछी जा रही थी तो वो भी उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे जहां एसडीएम ने डीईओ बीईओ और शिक्षकों की क्लास बच्चों के सामने लगा ली, शिक्षक ये कह रहे थे कि वो दौड़ दौड़ कर पढ़ाते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर शिक्षकों के 13 पोस्ट खाली हैं और यहां के शिक्षकों को विभाग द्वारा यहां पर अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है यहां पर संस्कृत हिंदी सहित अन्य शिक्षकों की कमी है छात्र नमन ने बताया कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या फिर हाइ स्कूल सभी जगह शिक्षकों की कमी यहां पर है।

क्या कहता है प्रशासन

सुबह 10 बजकर 30 मिनट से बच्चों ने स्कूल में ताला लगाकर रखा हुआ था जिसके बाद से शिक्षा विभाग के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भी मौके पर पहुंची इसके साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रही घंटों तक यहां पर बच्चे प्रदर्शन करते रहे बच्चों की हड़ताल खत्म कराने यहां पर प्रशासन मेहनत करती रही दोपहर तक बच्चे बिस्किट और मिक्चर खाकर अडिग रहे।

एसडीएम प्रतिमा ठाकरे ने कहा कि निष्कर्ष निकालने में हम लगे हुए हैं हम बच्चों की सुविधा के लिए ही यहां पहुंचे हुए हैं शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी और भवन निर्माण शासन स्तर का मामला है एसडीएम ने बताया कि यहां पर दो शिक्षकों की व्यवस्था वर्तमान में कर दी गई है और भवन निर्माण के लिए जो स्वीकृत है उसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है कि कैसे जल्द से जल्द निर्माण हो वही जिला शिक्षा अधिकारी ने भी प्रारंभिक शिक्षक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाए जाने की बात कही तब जाकर ग्रामीणों ने हड़ताल खत्म किया।

शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

अलग अलग स्कूलों से अनुपस्थित मिले दस शिक्षक

भाटापारा बलौदा बाजार। भाटापारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी की औचक निरीक्षण में अलग अलग स्कूलों से अनुपस्थित मिले दस शिक्षक शिक्षिका बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षिका जिसमे एक प्रधान पीठिका सहित दो शिक्षक सामिल,विकास खंड शिक्षा अधिकारी राम जी पाल, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी , बीआरसी एवं संकुल समन्वयको के द्वारा विकासखंड के विभिन्न स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण एवं अवलोकन किए गए जिसमें प्रार्थना में बहुत से शिक्षक अनुपस्थित मिले इस पर विकास का शिक्षा अधिकारी के द्वारा कारण बताओ नोटिश जारी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों में प्राथमिक शाला देवरी से विजयलक्ष्मी वर्मा, अभिलाषा शर्मा, आशा बंजारे, मिडिल स्कूल माता देवालय से प्रधान पाठक प्रेमा मसीह, जय श्री कलेत, उषा कोटरे, उषा ध्रुव, श्यामलाल वर्मा, प्राथमिक शाला लाल बहादुर।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर होगी भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और गरियाबंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती निकली गई। एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के तीन रिक्त पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। वहीं गरियाबंद अंतर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र के एक रिक्त पद में भर्ती की जाएगी।

एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) के परियोजना अधिकारी ने बताया कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के तीन रिक्त पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2024 तक आमंत्रित किये गये हैं। जिसकी सूची एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आयुक्त नगर पालिका निगम अम्बिकापुर के नोटिस बोर्ड में

चस्पा कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की भर्ती संत मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 04 मुक्तिपारा आंगनबाड़ी केंन्द्र, गौरी पारा वार्ड क्रमांक 28 बंगालीपारा-02 में एवं अग्रसेन वार्ड क्रमांक 37 बण्ड बहरा में होगी। उन्होंने बताया कि उक्त पदों पर केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। वे अपना आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय अम्बिकापुर (शहरी) में कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय पर जमा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित अवधि तक भेज सकते हैं। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें एवं अहर्ताओं के सम्बन्ध में परियोजना कार्यालय, नगर पालिका निगम अम्बिकापुर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

दूसरी ओर एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद अंतर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र के 01 रिक्त पद में भर्ती के लिए 28 अक्टूबर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केन्द्र बादीमार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 01 रिक्त पद की पूर्ति किया जाना है। जिसके लिए पात्र आवेदिकाओं से आवेदन आमंत्रित किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि आवेदन करने के लिए नियम व शर्तें परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है तथा संबंधित स्थलों से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक कार्यालयीन समय में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय गरियाबंद स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं।

सूरजपुर कांड का आरोपी कुलदीप साहू गिरफ्तार

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में आरक्षक की पत्नी और बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी और आखिरकार साइबर टीम के सहयोग से बलरामपुर पुलिस ने कुलदीप साहू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि बलरामपुर एसपी को जैसे ही आरोपी की लोकेशन और गतिविधियों की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत साइबर टीम को सक्रिय किया। टीम की तत्परता और तकनीकी सहयोग के बाद कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से हत्याकांड की जांच में एक बड़ा मोड़ आया है, और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। नाराज भीड़ ने कल आदतन आरोपी कुलदीप साहू के घर को आग के हवाले कर दिया था। आक्रामक भीड़ ने एसडीएम जगन्नाथ वर्मा के साथ मारपीट की थी, वहीं एसपी के साथ धक्कामुक्की करने का मामला सामने आया था।

लोहारीडीह घटना की सीबीआई से जांच की मांग न्याय के लिए आमरण अनशन पर बैठी पार्वती

कवर्धा। लोहारीडीह आगजनी केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पार्वती साहू ने की है। पार्वती साहू समाज से आती है और साहू प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष है। पार्वती अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी है। कवर्धा के राजीव गांधी पार्क में अनशन पर बैठी पार्वती को साहू समाज का भी समर्थन मिल रहा है। इस बात का दावा खुद पार्वती साहू ने भी किया है। अनशन पर बैठी महिला का कहना है कि लोहारीडीह केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जेल में जो भी निर्दोष लोग बंद हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पार्वती ने कहा कि जबतक निर्दोषों को छोड़ा नहीं जाता उनका अनशन जारी रहेगा।

लोहारीडीह केस की सीबीआई से जांच की मांग अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी पार्वती साहू का कहना है कि उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है। शासन की ओर से कोई उनसे बातचीत के लिए आएगा तो अपनी मांगें उनके सामने रखेगी। पार्वती का कहना है कि मृतक शिव प्रसाद साहू ऊर्फ कचरू साहू के शव को दोबारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले

की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अनशन पर बैठी महिला का कहना है जबतक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तबतक उनका अनशन जारी रहेगा।

पार्वती साहू की आठ मांगें

1. मृतक शिवप्रसाद साहू उर्फ कचरु साहू के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए।
2. लोहारीडीह घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए।
3. लोहारीडीह में जिन तीन लोगों की जान गई है उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले।
4. मृतक शिवप्रसाद साहू, प्रशांत साहू, रघुनाथ साहू के परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक एक करोड़ का मुआवजा मिले।
5. प्रशांत साहू की मौत के जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी कार्रवाई हो।
6. घटना की न्यायिक जांच कर दोषियों को कठोर सजा मिले, निर्दोषों को रिहा किया जाए।
7. मृतक के घर में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
8. प्रभावित गांव में शांति व्यवस्था और भाईचारा फिर से कायम करने का प्रयास किया जाए।

लोहारीडीह में क्या हुआ था-कवर्धा के लोहारीडीह में साहू समाज के शिवप्रसाद साहू के घर में भीड़ ने आग लगी दी थी जिससे कचरू साहू की मौत हो गई। लोहारीडीह के ही रघुनाथ साहू की लाश मिलने के बाद गांव में हंगामा हो गया। परिजनों और गांव वालों का आरोप था कि मृतक ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। लोहारीडीह आगजनी केस में पकड़े गए आरोपी की मौत होने के बाद नाराज साहू समाज ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत हुई है। इस घटना में आरोपी बनाए गए अभी भी कई लोग जेलों में बंद हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पुलिस अधीक्षक के नाम पर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

कोंडागांव। कोण्डागांव पुलिस और सायबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव, वाय अक्षय कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसा ऐंठ रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को हरियाणा के नूंह जिले से पकड़ा गया है। 7 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी प्रकाश नारायण सिंह ने थाना कोण्डागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे 'Akshay Kumar IPS' नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी, जिसे उसने स्वीकार किया। इसके बाद, 3 अक्टूबर को आरोपी ने अशोक कुमार नामक एक व्यक्ति का स्थानांतरण होने की बात कहकर उसका सामान बेचने का झांसा दिया और प्रार्थी से पैसे जमा करवाए। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक टीम गठित कर सायबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया। लगातार तीन दिन तक हरियाणा के नूंह जिले में आरोपी की लोकेशन ट्रैक करने के बाद, पुलिस ने ग्राम देवला नगली से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

कर्मा पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हैं अभिन्न हिस्सा

सूरजपुर। प्रतापपुर के परसावर ग्राम के सिलौटा स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय आदिवासी समाज कर्मा महोत्सव शामिल हुई महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कर्मा पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है, जो प्रकृति की पूजा और सामूहिकता का प्रतीक है। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को कर्मा त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कर्मा देवता की पूजा की। मंत्री ने इस पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह हमारे समर्पण और एकता का प्रतीक है। आदिवासी समाज का प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम हमें एकजुट करता है और सामूहिक प्रयास से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने प्रकृति की रक्षा और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री व बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े एवं प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते उपस्थित थी।

बलरामपुर रामानुजगंज नपं में 75 वर्ष बाद लग रहे विद्युत पोल

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज में आजादी के 75 वर्ष के बाद नगर में पहली बार ऐतिहासिक स्तर पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल की पहल पर नगर के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक के वार्डों में 1000 से अधिक नए विद्युत खंभे लगाए जा रहे है। दीपावली के पूर्व विद्युत खंभे लगाए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि नगर के वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 15 तक कई ऐसे जगह है जहां दशकों से विद्युत पोल लगाने की मांग की जा रही थी। परंतु अब तक विद्युत पोल नहीं लग पाया था लकड़ी और बांस के सहारे घरों तक विद्युत आपूर्ति के लिए तार लगे हुए थे। साथ ही कई वार्डों में विद्युत तार करीब 5 दशक पुराना था जिस कारण तार भी जर्जर स्थिति में होते जा रहा था यहां तक की तार भी लूज होकर झूलने लगा था जिससे आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। वार्डवासियों के द्वारा हमेशा विद्युत पोल लगवाने एवं तार को बदलवाए जाने की मांग की जाती रही थी।

बारनवापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन 21 से 23 तक

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से बारनवापारा अभयारण्य में तीसरी बाररनवापारा बटरफ्लाई मीट हो रही है। इसका आयोजन 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। बटरफ्लाई मीट का उद्देश्य बारनवापारा अभयारण्य के विभिन्न आवासों में तितलियों की विविधता का पता लगाना है। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे के अध्ययनों के लिए प्रमुख हॉट स्पॉट स्थापित करने में मदद मिलेगी। बटरफ्लाई मीट के लिए 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन करना होगा। बारनवापारा बटरफ्लाई मीट में शामिल होने के लिए प्रतिभागी, वन विभाग द्वारा जारी क्यूआर कोड को स्कैन कर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए आयु सीमा 18 से 60 साल तय की गई है। सभी प्रतिभागियों को रोजाना 10 से 15 किलोमीटर चलने में सक्षम होना अनिवार्य है। प्रतिभागियों को तितली प्रजाति का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है। प्रतिभागियों का चयन बारनवापारा अभयारण्य बटरफ्लाई मीट 2024 टीम करेगी। इस टीम का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

पत्नी को रील बनाने का शौक पड़ा महंगा

बलौदाबाजार। जिले के गिधपुरी थाना क्षेत्र के जुनवानी गांव के पास सोमवार सबुह एक महिला की खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। गिधपुरी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मृतिका 29 साल की ज्योति रात्रे है। वह अपने पति धीरज रात्रे के साथ तेलासी गांव में रहती थी। ज्योति रात्रे को रील बनाने का शौक था। वह कई तरह के रील वीडियो बनाती थी, जिसे लेकर उसके पति को आपत्ति थी। अपनी पत्नी के वीडियो रील बनाने से पति नाराज था। इसके अलावा हत्यारे पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था। अपने शक के वजह से ही उसने अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मायके ले जाने के बहाने पति धीरज ने पत्नी ज्योति को बाइक पर बिठाया और तेलासी से बलौदाबाजार जा रहा था। जुनवानी के पत्थर खदान के पास पहुंचते ही उसने पत्नी की हत्या कर दिया।

समग्र शिक्षा कांकेर में लेखापाल पद पर निकली भर्ती

कांकेर। समग्र शिक्षा कांकेर भर्ती के अंतर्गत जिले के 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालयों में पूर्णकालीक लेखापाल पद पर भर्ती निकाली गई है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य अहर्ताओं की पूर्ति करने वाले इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन विभाग में दे सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी जिले की वेबसाइट kanker.gov.in पर देख सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता- समग्र शिक्षा कन्या आवासीय विधालयों मे लेखापाल (अकाउंटेंट) के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुएशन (वाणिज्य विषय) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही लेखा

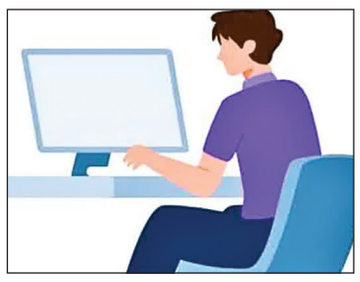

संबंधी कार्य के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। लेखापाल परद के लिए चयनित अभ्यर्थी को 25000/- प्रतिमाह एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। समग्र शिक्षा कांकेर में लेखापाल के लिए निकली भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी के लिए जिले की अधिकारिक वेबसाइट kanker.gov.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए कार्यालय, जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 26, जिला पंचायत परिसर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छग) के नाम भेज सकते हैं। अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2024 को शाम 5.00 बजे तक आवेदन जमा करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन या ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुम्बई-न्यूयार्क विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने का जुड़ा तार राजनांदगांव से

राजनांदगांव। इंडिगो की इंटरनेशनल मुम्बई-न्यूयार्क विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले का तार राजनांदगांव से जुड़ा मिला है और मुंबई पुलिस की एक टीम ने ट्वीट करने वाले मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हुए राजनांदगांव पहुंची और राजनांदगांव पुलिस की मदद से नाबालिग को गिरफ्तार कर अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग साइबर मामले में काफी जानकार है। इससे पहले उसने राजनांदगांव के एक पत्रकार कमलेश सिमनकर का एकाउंट भी हैक कर लिया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में राजनंदगांव रेंज आईजी दीपक झा ने कहा कि फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में मुम्बई पुलिस की एक टीम जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस का टीम को पूरा सहयोग है। मुम्बई पुलिस को जिस मोबाइल से धमकी मिली थी, उसे भी ढूंढ निकाला। साइबर जांच में यह बात सामने आई कि नाबालिग ने डोंगरगांव के रहने वाले फजलुद्दीन नामक एक व्यक्ति के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया और उसमें उसने फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी ट्वीट कर दी। इससे उड़ान प्रभावित हुई।

जंगली सुअर के लिए छोड़ा था करंट, चपेट में आए दो बाइक सवार

कोरबा। जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेला में सोमवार की देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो ग्रामीण युवकों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना बालको थाना पुलिस को दी गई।

बताया जा रहा है कि गांव से गुजरे 11 केवी करंट प्रवाहित तार से शिकारियों के द्वारा शिकार करने के लिए जीआई तार को बिछाया गया था। तार बहुत नीचे और जमीन से लगा हुआ था। इसी रास्ते से मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम टापरा की ओर से बेला आ रहे दो युवक नारायण कंवर पिता करम सिंह 35 वर्ष व टिकेश्वर राठिया पिता बृजलाल 32 वर्षीय दोनों करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गए।

जहां दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

यह मार्ग आम रास्ता होने के कारण लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा थी। घटना के दौरान राहगीरों की नजर उन पर पड़ी और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जहां मौके पर पहुंचे करंट प्रवाहित तार को पहले अलग किया। उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं इसकी सूचना मृतक के परिजनों को भी दिए जहां मौके पर पहुंचे।

घटना की सूचना मिलते ही बालको थाना में पदस्थ एएसई माखन लाल पात्रे और प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। मौके तक चारपहिया वाहन जाने का रास्ता नहीं है। पुलिस किसी तरह घटनास्थल पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए रात करीब 10:45 बजे पंचनामा बाद शव को जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा स्ट्रेचर में दोनों शवों के साथ करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई, तब जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। मंगलवार को सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतकों के परिजनों में कोहराम व गांव में शोक मिश्रित सन्नाटा पसर गया है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। राष्ट्र के लिए उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि डॉ. कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने देश के अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी। उनके प्रयासों से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉ. कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई है।

राज्य सेवा परीक्षा-2023 का इंटरव्यू और वेरिफिकेशन हुआ स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2023 के अंतर्गत 242 पदों के लिए निर्धारित दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। यह 14 अक्टूबर से पांच नवंबर 2024 के बीच होना था। जिसे स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय आयोग में नए सदस्यों और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बोर्ड का पुनर्गठन करने के कारण लिया गया है। बता दें कि पीएससी में नए सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसके वजह से पीएससी में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ गई। पुराने सदस्यों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया गया था। अब फिर से साक्षात्कार के लिए बोर्ड का गठन होगा, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार आयोजित होगी। यही वजह है कि राज्य सेवा परीक्षा-2023 के लिए पूर्व में निर्धारित दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू की प्रक्रिया को स्थगित किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार संशोधित साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जारी की जाएगी।

पीएचई में 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू, विभाग ने व्यापमं को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त विभाग से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 261 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को पत्र भेजा जा रहा है। पीएचई में अभियंताओं और हैंडपंप तकनीशियनों सहित राज्य स्तरीय 181 और अराज्य स्तरीय 80 पदों पर भर्ती होनी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य स्तरीय पदों के तहत उप अभियंता (सिविल) के 118 पदों, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के दस, अनुरेखक के 37, केमिस्ट के 12, सहायक ग्रेड-3 और वाहन चालक के दो-दो पदों पर चयन के लिए व्यापमं को पत्र लिखा जा रहा है। वहीं अराज्य स्तरीय पदों के अंतर्गत हैंडपंप तकनीशियन के 50 पदों, सहायक ग्रेड-3 और वाहन चालक के दस-दस पदों तथा प्रयोगशाला सहायक और ट्रक चालक के पांच-पांच पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापमं को पत्र लिखा जा रहा है।

मस्तूरी एसडीएम सिन्हा होंगे राज्यमंत्री तोखन के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी

रायपुर। केंद्रीय आवास, शहरी कार्य मंत्री राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू के निज स्टाफ में मस्तूरी एसडीएम अमित सिन्हा (डिप्टी कलेक्टर) को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी (ए पी एस) नियुक्त किया गया है। केंद्रीय आवास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में सिन्हा रिलीव करने के लिए निर्देशित किया गया है। अमित सिन्हा संसदीय क्षेत्र बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ संबंधी विभागीय विषयो एवं कार्यों को देखेंगे।

मुख्यमंत्री साय का जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर किया गया आत्मीय स्वागत

जगदलपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे। यहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय का स्वागत वनमंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप, सांसद कांकेर श्री भोजराज नाग, विधायक श्री किरणदेव, कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेण्डी, विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप,पूर्व विधायक श्री संतोष बाफना,श्री लच्छुराम कश्यप, श्री सुभाऊ कश्यप के साथ-साथ बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी., सीसीएफ़ श्री आरसी दुग्गा, कलेक्टर श्री हरिस एस.,एसपी श्री शलभ कुमार सिन्हा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने किया।

रायपुर दक्षिण सीट भाजपा का है अभेद्य किला, कांग्रेस को करिश्मे की उम्मीद

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव, जानिए इस सीट का सफरनामा

रायपुर। कभी रायपुर टाउन के नाम से जानी जाने वाली सीट अब रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती है। बीजेपी का इस सीट पर सालों से दबदबा बरकरार है। इस विधानसभा सीट के सियासी सफर को देखें तो 1977 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर टाउन सीट पर जनता दल और रायपुर सीट पर जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 1977 के चुनाव में रायपुर टाउन सीट से बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। यह सीट जनता पार्टी के खाते में गई। जनता पार्टी से रजनी डीपी उपासने ने जीत दर्ज की। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे।

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का सियासी सफरनामा

1977 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब देश में छात्र आंदोलन का पूरा असर था। रायपुर टाउन सीट पर जनता दल जीती तो रायपुर सीट पर जनता पार्टी ने विजय हासिल की। जनता पार्टी की उम्मीदवार रजनी डीपी उपासने को 17 हजार 925 वोट मिले जो की कुल मतदान का 41।6 फीसदी रहा। इसी सीट से खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर प्रसाद को 30।3 फीसदी वोट मिले।

पहली बार बीजेपी ने 1980 में यहां चुनाव लड़ा

1980 में पहली बार भाजपा ने रायपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा किया। 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर टाउन और रायपुर रुरल दोनों सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर टाउन की सीट पर पहली बार अपना प्रत्याशी खड़ा किया। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1980 से ही बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरु कर दिया। पार्टी को 1980 में 27 फीसदी वोट हासिल हुए। बीजेपी की ओर से बालू भाई पटेल मैदान में थे।

1985 में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने किया कब्जा

1985 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रायपुर टाउन और रायपुर ग्रामीण दोनों सीटों पर जीत दर्ज की।1980 में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बीजेपी ने 1985 में भी बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी पकड़ और मजबूत की। भारतीय जनता पार्टी की और से मैदान में उतरे वीरेंद्र पांडे चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। साल 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में टाउन सीट बीजेपी के खाते में गई। आपको बता दें वर्तमान में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पहले रायपुर टाउन सीट और रायपुर ग्रामीण सीट के रूप में बंटी रही।

बृजमोहन अग्रवाल ने खिलाया 1990 में कमल

1990 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल ने इस सीट को जीतकर बीजेपी का परचम लहराया। साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल मैदान में उतरे और कमल खिलाया। 1998 में भी बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की। राज्य का बंटवारा होने के बाद 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में रायपुर टाउन विधानसभा सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। बृजमोहन अग्रवाल फिर विजय बने। बीजेपी की पकड़ इस सीट पर लगातार बढ़ती गई।

2008 तक रायपुर में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें थी

2008 तक रायपुर में सिर्फ दो विधानसभा सीट हुआ करती थी जो रायपुर टाउन और रायपुर रूरल सीट थी। 2008 में रायपुर को कुल चार विधानसभा सीटों में बांट दिया गया जिसमें रायपुर ग्रामीण, रायपुर सिटी वेस्ट, रायपुर सिटी नॉर्थ, और रायपुर सिटी साउथ में बांटा गया। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी यह सीट भाजपा के खाते में ही गई। बीजेपी ने जो जीत का जो सिलसिला शुरु किया वो लगातार आगे भी जारी रहा। साल 1990 के बाद बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से विजयी योद्धा बन गए। हर बार जीत उनके ही खाते में जाते रही।

अजेय योद्धा बने बृजमोहन अग्रवाल, कमल का बन गया किला

बृजमोहन अग्रवाल ने जो जीत का सिलसिला शुरु किया वो सिलसिला 2024 तक जारी रहा। अब 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। मतदान की तारीख आने के बाद अब उम्मीद है जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। अब देखना ये है कि जो विरासत जीत की बृजमोहन अग्रवाल ने खड़ी की है वो बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस कोई करिश्मा करती है। नतीजे तो जनता के हाथों ही तय होना है।

मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव को राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। श्री साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में वन मंत्री श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों ने भेंटकर उन्हें शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर अधिकारियों ने उन्हें स्पोर्ट्स किट भी भेंट किया।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, एडिशनल पीसीसीएफ श्री सुनील मिश्रा, एडिशनल पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय, एडिशनल पीसीसीएफ श्रीमती संजीता गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती शालिनी रैना, सीसीएफ श्री राजू अगासिमनी भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता की नोडल अधिकारी श्रीमती शालिनी रैना (मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन व आईटी) ने बताया कि यह एक वृहद व प्रतिष्ठित आयोजन है जो वनों की सुरक्षा व वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर समर्पित है, जिसमें देशभर के अनेक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी के 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देशभर से करीब 3 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सतत प्रयासरत है।

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन राजधानी के कोटा स्थित स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान और युवाओं में स्काई के नाम मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव शामिल होंगे। साथ ही आयोजन के समापन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी वीडियो जारी कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के वन सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई देते हुए आयोजक वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को शुभकामनाएं प्रेषित की है।

बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम

जगदलपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने साफा एवं गज़माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री ने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। साथ ही एंबुलेंस के लिए बनी डिजिटल वेबसाइट, ट्रांजिस्ट हॉस्टल का लोकार्पण एवं चेंबर पत्रिका (ई-पत्रिका) का विमोचन किया।

शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचन नामावली तैयार करने व्यापक प्रचार-प्रसार करें : निर्वाचन आयुक्त

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षण किये जाने का कार्यक्रम प्रक्रियाधीन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी जिला के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने कहा है, जिससे शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।

उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। निर्वाचन आयुक्त सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली के प्रचार-प्रसार के साथ ही 16 अक्टूबर को अपने-अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के माध्यम से निर्वाचन से जुड़ी जानकारी देने कहा है।

निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हांकित विविध स्थानों की जानकारी, दावें एवं आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थलों की पंचायतवार, निकायवार एवं वार्डवार कुल संख्या की विस्तृत जानकारी देने कहा है। इसी तरह दावें एवं आपत्तियों को प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने हेतु निर्धारित तिथियां, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिले द्वारा %जाबो' अंतर्गत किये गये जागरूकता संबंधी कार्य सहित निर्वाचन संबंधी आवश्यक विषय पर जानकारी मीडिया को देने कहा है। जिससे मीडिया के माध्यम से निर्वाचन संबंधी जानकारियां लोगो तक पहुंच सके।

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में सूर्य कुमार यादव और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन रायपुर के कोटा स्थित स्टेडियम में होगा। वहीं 20 अक्टूबर के समापन कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर शामिल होगी।

इस आयोजन में दो स्टार खिलाड़ियों की उपस्थिति से विभिन्न राज्यों से आने वाले वन विभाग के प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस आयोजन की नोडल अधिकारी शालिनी रैना (मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन व आईटी) ने बताया कि यह एक वृहद और प्रतिष्ठित आयोजन है जो कि वनों की सुरक्षा और वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर समर्पित है, जिसमें देशभर के अनेक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं।

सभी खिलाड़ियों के ठहरने और खेल आयोजन में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। राजधानी के विभिन्न स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में अनेक आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रतिभागियों को यह पूरा आयोजन और छत्तीसगढ़ प्रदेश का अतिथि सत्कार पसंद आएगा।

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देशभर से करीब तीन हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सतत प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी वीडियो जारी कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के वन सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देते हुए आयोजक वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के छत्तीसगढ़ आगमन पर भी हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के आने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए यह एक सुअवसर होगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आज होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन

■ राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही करने के दिए निर्देश

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है।

आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोडने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।

प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बस्तर मण्डल, जगदलपुर

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-
निविदा डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि:- 25/10/2024

स. क्र.	नि.आ.सू.क्र./ नि.आ.सू दिनांक	सिस्टम निविदा निविदा का क्रम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमाति लागत (रूपये लाख में)
01	02	03	04	05
1	43/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159713 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 जगदलपुर के अन्तर्गत गैर आवासीय भवनों मुख्यालय क्र. 01, 02, 03 एवं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भवनों का वार्षिक संधारण कार्य।	43.00
2	44/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159718 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 जगदलपुर के अन्तर्गत गैर आवासीय भवनों मुख्यालय क्र. 01, 02, 03 एवं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भवनों का वार्षिक संधारण कार्य।	43.00
3	45/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159719 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 जगदलपुर के मुख्यालय क्र. 01, 02, 03 सड़क सामग्री सप्लाई कार्य।	15.00
4	46/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159720 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 जगदलपुर के मुख्यालय क्र. 01, 02, 03 अन्तर्गत गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	30.00
5	47/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159721 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 जगदलपुर के मुख्यालय क्र. 01, 02, 03 एवं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	50.00
6	48/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159722 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 जगदलपुर के अन्तर्गत डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	40.00
7	49/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159723 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 03 जगदलपुर के अन्तर्गत (बकावण्ड उपखण्ड) आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	20.00
8	50/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159724 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 03 जगदलपुर के अन्तर्गत (तोकापाल उपखण्ड) आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	20.00
9	51/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159725 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 03 जगदलपुर के अन्तर्गत (तोकापाल एवं बकावण्ड उपखण्ड) आवासीय एव गैर आवासीय भवनों का वार्षिक संधारण कार्य।	10.00
10	52/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159726 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 02 जगदलपुर के अन्तर्गत (धरमपुरा, आड़ावाल/नगननार नानगुर उपखण्ड) गैर आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	26.00
11	53/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159727 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 02 जगदलपुर के अन्तर्गत (धरमपुरा, बोधघाट, आड़ावाल / नानगुर उपखण्ड) आवासीय भवनों का रंगाई-पोताई कार्य।	36.00
12	54/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159729 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 02 जगदलपुर के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का वार्षिक संधारण कार्य।	20.00
13	55/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159730 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 02 जगदलपुर के अन्तर्गत आवासीय भवनों का वार्षिक संधारण कार्य।	15.00
14	56/2024-25 दिनांक 10/10/2024	159731 (प्रथम आमंत्रण)	उपसंभाग क्र. 01 बीजापुर के अन्तर्गत कलेक्टोरेट ऑफिस भवन का रंगाई-पोताई एव साधारण मरम्मत कार्य।	10.00

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

जी-242503163/7

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, बस्तर मंडल जगदलपुर

कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम हकीकत कम, चुनावी ज्यादा

योगेन्द्र योगी

केंद्र और ज्यादातर राज्यों से चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने इतिहास से सबक नहीं लेने की ठान ली है। यही वजह है कि कांग्रेस का अभी तक अल्पसंख्यक मोह खत्म नहीं हुआ है। अल्पसंख्यकों के गैरकानूनी कामों में भी कांग्रेस उनका बचाव करती नजर आती रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही अकेली नहीं है, बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिमों के अपराधों को माफ करने के पक्ष में रहे हैं। बेशक अपराध आतंकवाद से जुड़े हुए ही क्यों न हों। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दंगा करने, थाने पर हमला करने, आगजनी और तोड़-फोड़ जैसे गंभीर आरोपों में शामिल मुस्लिम समुदाय के आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रेम को उजागर किया है। लगातार हारने के बाद भी कांग्रेस को डूबती नैया का सहारा मुसलमान वोट बैंक ही नजर आता है। यह बात दीगर है कि इस वोट बैंक के दावेदार कई राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से भाजपा देश में हिन्दू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही है। कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद 43 केसों को रद्द करने का फैसला लिया। इसमें एक मामला हुबली पुलिस स्टेशन में तोड़-फोड़ से जुड़ा हुआ है। 16 अप्रैल, 2022 को हुबली में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट लिखने वाले युवक को पुलिस गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लेकर आई, कुछ देर में वहां मुस्लिम समाज की भीड़ जमा हो गई और आरोपी को भीड़ को सौंपने की मांग को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद हिंसा हुई थी, पुलिस स्टेशन और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था, साथ ही आस-पास की दुकानों में तोड़-फोड़ की गई। इस हिंसा में 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। ए.आई.एम.आई.एम. के नेता आरिफ और 138 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने पहली बार ऐसा नहीं किया। जब भी देश के संविधान और कानून को समानता से लागू करने की बात होती है, कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों का दूसरे चश्मे से देखती रही है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। यह जानते हुए भी कि विशेष राज्य और कानून की आड़ में इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी वारदातें कर रहे हैं। इन पाक परस्त आतंकियों को बचाने के लिए भाड़े के पत्थरबाज सुरक्षा कवच का काम करते रहे हैं। इस विशेष प्रावधान के हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गईं। साथ ही सुरक्षा बल और पुलिस काफी हद तक आतंकियों पर नकेल कसने में कामयाब रहे। यह मुद्दा देश की एकता-अखंडता से जुड़ा होने के बावजूद कांग्रेस ने इसे हटाने पर कायम नैशनल कांफ्रैंस के साथ महज मुस्लिम वोट बैंक की खातिर चुनावी गठबंधन किया। इसी तरह अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शणार्थियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सहानुभूति का रुख रखा। कांग्रेस का कहना था कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप मानवीयता के आधार पर रोहिंग्या मुस्लिमों को मदद भेजें और दूसरी तरफ उनको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल बताएं, सरकार किसी एक नीति पर आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट बैंक की खातिर मुस्लिम प्रेम नया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ही सरकार थी जिसने शाहबानो केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद उस पर कानून नहीं बनाया। इस पर मौजूदा भाजपा की केंद्र सरकार ने कानून बनाया। तीन तलाक के मुद्दे पर भी कांग्रेस का यही आलम रहा। कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे पर कानून नहीं बनाया। शाहबानो ने अदालत से न्याय की मांग की थी कि तीन तलाक के बाद तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होती है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 23 अप्रैल, 1985 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्ड के आदेश के खिलाफ जाते हुए शाहबानो के पति को आदेश दिया कि वह अपने बच्चों को गुजारा भत्ता दे। मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए थे। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में तीन तलाक को वापस करने का वायदा किया। इसी दोहरी नीति के कारण भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रही है। कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाए। आजादी के बाद कांग्रेस ने देश में 50 साल से ज्यादा शासन किया है। इस अवधि में ज्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। इसके बावजूद देश में साक्षरता की दर, मुस्लिम महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम हकीकत कम चुनावी ज्यादा साबित हुआ है।

इंडी अलायंस पर हरियाणा के साइड-इफेक्ट्स

डॉ. प्रकाश हिंदुस्तानी

हरियाणा चुनाव में इंडी अलायंस के सपनों की कब्रगाह तैयार हो गई। अब महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली की चुनौती सामने है! चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ईवीएम का संताप जता चुकी। राहुल गांधी समीक्षा बैठक में पार्टी के ही कई नेताओं की लू उतार चुके। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस को उम्मीद थी और इंडी अलायंस के कई दलों को लगता था कि कांग्रेस उनके लिए बड़े भाई की भूमिका निभाती रहेगी, लेकिन अब छोटे भाइयों ने ही दूर छिटकना शुरू कर दिया। घरों में बंटवारे की हर दीवार की शुरुआत मामूली शिकायतों से होती है। यहां भी हाल यही है कि हर छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा बलिदान चाहता है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने भारतीय राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस, जो एक समय भारत की सबसे प्रभावी राजनीतिक पार्टी थी, अब लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। यह हार कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य चुनाव की हार नहीं है, बल्कि इससे पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति और राहुल गांधी की राजनीतिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है।हरियाणा में कांग्रेस की हार ने पार्टी की राष्ट्रीय स्थिति को भी कमजोर किया है। जहां कांग्रेस की स्थिति पहले ही कई राज्यों में कमजोर हो चुकी है, इस हार ने पार्टी के भविष्य को लेकर और भी अनिश्चितता बढ़ा दी है। कांग्रेस को न सिर्फ आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके संगठनात्मक ढांचे में भी कमजोरी नज़र आ रही है। यह हार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के रूप में देखी जा सकती है। पार्टी को जनता से जुड़े मुद्दों पर और आक्रामकता से काम करना होगा, विशेषकर ग्रामीण और किसान वर्ग के मुद्दों पर जो हरियाणा जैसे राज्यों में अहम हैं। पार्टी का संगठन जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना ही होगा।

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार किया था, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला था। लेकिन हरियाणा की हार ने उनके नेतृत्व की चुनौतियों को फिर से उजागर किया है। यह हार एक संकेत है कि सिर्फ भावनात्मक और प्रतीकात्मक राजनीति पर्याप्त नहीं है; जमीनी स्तर पर ठोस रणनीतियों और संगठन की जरूरत होती है। राहुल गांधी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर से भी है। उन्हें अब न सिर्फ चुनावी रणनीतियों में बदलाव करना होगा, बल्कि जनता के बीच अपनी विचारधारा को और मजबूत तरीके से पेश करना होगा। किसानों, युवाओं, और महिलाओं जैसे महत्वपूर्ण वोट बैंक पर ध्यान देना उनके लिए आवश्यक होगा। हरियाणा की हार का असर सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रभाव इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सफलता की उम्मीद कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, क्योंकि यह गठबंधन भाजपा के खिलाफ एक साझा विपक्ष के रूप में उभरा है। हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में हार से गठबंधन की एकता और स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं।

यह हार गठबंधन के अन्य दलों के लिए एक सीख हो सकती है कि उन्हें जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और रणनीतियों पर काम करना होगा। अगर कांग्रेस खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पाती है, तो गठबंधन के अन्य सदस्य इस नेतृत्व पर प्रश्न खड़े कर सकते हैं। दूसरी ओर, हरियाणा में कांग्रेस की हार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एडीए) के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। भाजपा लंबे समय से अपने मजबूत संगठन और नेतृत्व के कारण हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और यह हार भाजपा के लिए भविष्य की राजनीतिक बढ़त के रूप में काम कर सकती है। एनडीए इस जीत को विपक्ष की कमजोरी के रूप में प्रचारित कर रहा है, जिससे आगामी चुनाव में उन्हें फायदा हो सकता है। यह गठबंधन अपने विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे को और मजबूती से पेश कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी गठबंधन कमजोर दिखाई देता है।

हरियाणा में कांग्रेस की हार भारतीय राजनीति के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे, चुनावी रणनीतियों और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के तरीकों पर गहराई से विचार करना होगा। राहुल गांधी को अपनी राजनीति को और स्पष्ट और प्रभावी बनाना होगा, ताकि पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया जा सके। इंडिया गठबंधन के लिए यह समय है कि वह अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करे, जबकि भाजपा और एनडीए इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस हार से विपक्ष के सामने नई चुनौतियां हैं, और सत्ता पक्ष के लिए नई संभावनाएँ। हरियाणा की हार भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य का प्रतीक है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह हार कांग्रेस, राहुल गांधी और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को कैसे प्रभावित करती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन के भीतर नए समीकरणों और चिंताओं को जन्म दिया है। यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी ध्रुव के रूप में उभरा था, लेकिन कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टी की लगातार हार से गठबंधन में तनाव और असमंजस बढ़ सकता है। आम आदमी पार्टी पहले ही हरियाणा में अपने रुख को साफ़ कर चुकी है।

समाजवादी पार्टी (सपा) उत्तर प्रदेश में एक मजबूत क्षेत्रीय दल है और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ कई मौकों पर सहयोग किया है, लेकिन हरियाणा की हार के बाद सपा की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। अखिलेश यादव का मुख्य ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है, जहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। अखिलेश इस स्थिति का फायदा उठाकर सपा को गठबंधन में और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। सपा का रुख अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वह गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका कैसे निभाती है। अगर कांग्रेस अपने राज्यों में चुनावी प्रदर्शन को बेहतर नहीं कर पाती है, तो सपा का रवैया कांग्रेस से दूरी बनाने की ओर भी बढ़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में एक अजेय नेता मानी जाती हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार से ममता बनर्जी को यह समझने का मौका मिल सकता है कि कांग्रेस अब कई राज्यों में प्रभावशाली नहीं रही है। ममता बनर्जी पहले भी कांग्रेस के प्रति स्वतंत्र और निर्णायक रुख अपनाती रही हैं। हरियाणा की हार के बाद ममता बनर्जी का कांग्रेस के प्रति सहयोग थोड़ा कमजोर हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी खुद की शक्ति पर निर्भर है, और ममता यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि गठबंधन के भीतर कांग्रेस पर उनकी निर्भरता कम हो। हालांकि, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में दोनों पार्टियों के हित एकजुट हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व की प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में एक प्रमुख पार्टी है, और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ लंबे समय से गठबंधन संबंध बनाए रखा है। हरियाणा की हार का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका संकेत यह हो सकता है कि कांग्रेस को अब अपने नेतृत्व की कमजोरी और संगठनात्मक ढांचे पर काम करना चाहिए। चार निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद अब उमर अब्दुल्ला के समर्थक विधायकों की संख्या 46 हो हो गई है। (पांच मनोनीत सदस्यों को नहीं गिना जाए तो)90 सदस्यों के सदन में उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने और बने रहने के लिए कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं है। उमर अब्दुल्ला रुख भी बीजेपी के लिए बदल रहा है और वे केंद्र से सहयोग करते हुए मोदी- मोदी की रट लगाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू-कश्मीर का मसला सबसे अहम है, और अगर कांग्रेस इस क्षेत्र के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करती है, तो गठबंधन में तालमेल बना रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस अपने अन्य राज्यों में कमजोर होती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बिना भी अपनी रणनीतियों पर विचार कर सकती है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का बिहार में अच्छा जनाधार है, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ सहयोग जारी रखा है। हरियाणा की हार के बाद, राजद का सहयोग कांग्रेस के साथ बना रह सकता है, लेकिन कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बने। तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं, और अगर कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करती है, तो राजद के साथ संबंध और बेहतर हो सकते हैं। अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है, तो राजद अपनी स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति को और अधिक प्रखर बना सकता है। बिहार में महागठबंधन तभी प्रभावी रहेगा जब कांग्रेस खुद को एक मजबूत भागीदार साबित करेगी।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का धड़ा एनडीए से अलग है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना ने साथ मिलकर काम किया है, और भाजपा को चुनौती दी है। हरियाणा की हार का शिवसेना पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि उद्धव ठाकरे गठबंधन के भीतर और अधिक भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। सामना के ताजे सम्पादकीय राहुल गांधी को राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं। शिवसेना का कांग्रेस के साथ संबंध सहयोगी बना रह सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे यह सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना की नेतृत्व भूमिका मजबूत हो। कांग्रेस को यह समझना होगा कि शिवसेना की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं महाराष्ट्र में कांग्रेस से आगे बढ़ सकती हैं, और यह गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की चुनौती हो सकती है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च। (निरुक्त 1 ।20।2) अर्थात् पहिले पहिल ऋषि स्वभावतः मन्त्रद्रष्टा थे अतः उन्होंने घर्म का साक्षात्कार किया था। अनन्तर मन्त्र देखने की सामर्थ्य न रखने वाले मुनियों को उन मन्त्रद्रष्टाओं ने उपदेश द्वारा मन्त्र दिये।

आगे चल कर उपदेश ग्रहण करने की शक्ति भी क्षीणप्रायः हो चली। तब बेद का साङ्गोपाङ्ग रहस्य जानने के लिये निरुक्त, व्याकरणादि अन्यान्य अङ्गों और उपाङ्गों की रचना हुई।

उपर्युक्त यास्कसम्मति के अनुसार ब्रह्मा और उनके मरीची आदि मानसिक पुत्र जिनका कि प्रायः विनियोगों में मन्त्रद्रष्टा रूप से उल्लेख मिलता है- साक्षात्कृतधर्मा कहे जा सकते हैं और इनके शिष्य प्रशिष्यों को उपदेश-पात्र कहा जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आरम्भ करके प्रथम व्यास के अवतार-काल तक वह त्रिकाण्डात्मक एक वेद गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा उपदिष्ट होता चला आया।

एक में अनेकत्व का व्यवहार- यहाँ इतना और भी विशेष समझ लेना आवश्यक है कि इस समय हम जो ऋ, यजुः, साम और अथर्व नामक भिन्न-भिन्न चार ग्रन्थ देख पाते हैं इनका इस प्रकार का मन्त्रसमुदायात्मक संग्रह आदिम व्यास से पूर्व नहीं हो पाया था। उस समय उस एक ही बृहत्काय श्रुति-सन्दर्भ के स्तुति-प्रधान मन्त्रों को ऋक् और यजन-प्रधान गद्यात्मक मन्त्रों को यजुः तथा गीति-प्रधान विशिष्ट मन्त्रों को साम नाम से स्मरण किया जाता था। पश्चात् अथर्वाङ्गिरस द्वारा प्रचरित आभिचारिक-मन्त्र समुदाय की भी अथर्व नाम से ख्याति हो गई थी। इस प्रकार एक ही ग्रन्थ चतुर्विध प्रकारता के कारण होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा नामक चार ऋत्विजों में विभक्त किया समझा जाता है।

क्रमशः ...

विश्व खाद्य दिवस

बाल मुकुन्द ओझा

विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1981 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी, कुपोषण और भुखमरी के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाना और सरकारों को सभी प्रकार की सहायता सुलभ करना है। बताया जाता है कि विश्व स्तर पर लाख प्रयासों के बावजूद गरीबी, कुपोषण और भुखमरी में कमी नहीं आयी और यह रोग लगातार बढ़ता ही गया। इसका मुख्य कारण अन्न की बर्बादी को बताया गया। खाद्यान्न बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मगर असल समस्या से हम अभी भी जूझ रहे हैं जिसके समाधान के बिना विश्व खाद्य दिवस मनाना बेमानी प्रतीत होता है। वर्तमान में विश्व गरीब और अमीर दो भागों में बंटा हुआ है। सच तो यह है कि अमीर देश लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों की गरीबी बढ़ती ही जा रही है। जब तक यह असन्तुलन खत्म नहीं होगा तब तक गरीबी और भुखमरी भी यथावत रहेगी। जरूरत इस बात की है कि संपन्न देश कमजोर देशों को सभी प्रकार की सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराएं तभी इस वैश्विक समस्या पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही साधन संपन्न लोग भोजन की बरबादी नहीं करें और बचा भोजन गरीब परिवारों को दें। मगर यह समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। गरीबी कैसे दूर हो यह प्राथमिक बात है। कुपोषण और भुखमरी गरीबी से जुड़ी हुई है। गरीबी दूर करने के सर्वांगीण प्रयास करने होंगे। इसे विश्व स्तर पर सुलझाना होगा तभी हम अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनने के लिए उन्नत कृषि प्रणाली को अपनाना होगा। देश का कृषि उत्पादन बढ़ाकर हम कई मौजूदा समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं।

यह दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है और इस दिन गरीबी और भूख की समस्या का निदान खोजने तथा जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भोजन बर्बाद न करें और इसका सम्मान करें क्योंकि आधी दुनिया मौलिक आवश्यकताओं के अभाव में जी रही है तथा काफी हद तक भुखमरी की शिकार है। विश्व समाज के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। विश्व में लोगों को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वे कुपोषण के दायरे से बाहर निकल कर एक स्वस्थ जीवन जी सकें। लोगों को संतुलित भोजन मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो। विश्व में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक नौ अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें करीब 80 फीसदी लोग विकासशील देशों में रहेंगे। एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और वह भूख से मर रहे हैं। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। दुनिया में पैदा किए जाने वाले खाद्य पदार्थ में से करीब आधा हर साल बिना खाए सड़ जाता है।

इस्राइल-हमास युद्ध में अपराधी कौन और सहयोगी कौन?

रामचंद्र गुहा

हमास ने 7 अक्तूबर, 2023 को इस्राइल के नागरिकों पर क्रूर हमला किया। इसमें 1,100 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से तीन-चौथाई आम लोग थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्राइल ने गाजा से लगे हमास के नियंत्रण वाले फलीस्तीनी क्षेत्र पर बमबारी की। तब लगा था कि इस्राइल कुछ समय बाद बमबारी बंद कर देगा, लेकिन यह बर्बर अभियान पूरे एक साल से जारी है। इस्राइली सेना के हमलों में 50,000 से अधिक फलीस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के दस लाख से अधिक निवासी अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। गाजा में तबाही मचाने के बाद अब इस्राइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया है। वहां भी उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की है कि हमले में आतंकवादी मारे जा रहे हैं या निर्दोष नागरिक। खास लोगों को खत्म करने की कोशिश में उसने सैकड़ों लेबनानी नागरिकों को मार डाला है और हजारों को बेघर कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इस्राइयल और हमास, दोनों को युद्ध अपराधों का दोषी माना है और यह बिल्कुल उचित भी है। पिछले अक्तूबर में हमास द्वारा किए गए नरसंहार को किसी भी ऐतिहासिक संदर्भ में न तो माफ किया जा सकता है और न ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। बदला लेने की कोशिश में उसने अंधाधुंध कार्रवाई और बमबारी की है। स्कूलों और अस्पतालों को नष्ट किया है। हजारों फलीस्तीनियों को मारने के अलावा भोजन, पानी और बिजली की आपूर्ति को रोककर या प्रतिबंधित कर अनगिनत लोगों को भुखमरी के

कगार पर पहुंचा दिया है।

गाजा में संघर्ष की कवरेज में मुख्य रूप से दो प्रतिस्पर्धी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है- इस्राइल और हमास। यह कॉलम उन समूहों या राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्होंने संघर्ष पैदा करने और उसे कायम रखने में भूमिका निभाई है। अक्सर अपराधों के मामले में अपराधी के पास सहयोगी होते हैं। तो फिर वे कौन लोग हैं, जिन्होंने एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इस्राइल की मदद की है?

हमास का प्रमुख सहयोगी ईरान और लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह है। प्रमुख पश्चिमी मीडिया नियमित रूप से इसका नाम लेकर उसे शर्मिंदा भी करता है। इसके बावजूद वह इस्राइल के सहयोगियों की पहचान करने से कतराता है। निस्संदेह इस्राइली सरकार के इन कृत्यों के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। उसने इस्राइल को लगातार सैन्य मदद दी है, उसे गाजा (और अब लेबनान) पर हमला जारी रखने के लिए जरूरी हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों के खिलाफ वीटो या मतदान करके इस्राइल को राजनयिक संरक्षण की भी पेशकश की है। अमेरिका की मिलीभगत के इन्कार का उदाहरण पिछले सप्ताह मैंने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साक्षात्कार में सुना। उनसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अनुभव के बारे में पूछा गया, जहां वह विजिटिंग प्रोफेसर हैं। पिछले साल उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो कुछ समय बाद ही कोलंबिया (और अन्य परिसरों) में छात्रों के शृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें मांग की गई कि इस्राइल गाजा पर बमबारी बंद करे और युद्ध विराम पर सहमत हो। सुश्री क्लिंटन ने इन विरोध प्रदर्शनों को इस आधार पर सिरे से खारिज कर दिया कि उन्हें 'बाहर' से समर्थन और वित्त पोषण प्राप्त था।

इस प्रदर्शन में बाहर के बिना बुलाए कुछ एजेंट जरूर थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों में से अधिकांश इसी विश्वविद्यालय के छात्र और संकाय सदस्य थे। इसके अलावा गाजा में महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में अपने पूर्वजों की पक्षपातपूर्ण प्रतिबद्धता के खिलाफ कई यहूदी छात्र भी शामिल हुए। हिलेरी क्लिंटन का इंटरव्यू लेने वाले फरीद जकारिया भी उनके सामने अपने तथ्यों को नहीं रख पाए। हिलेरी क्लिंटन को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि न्यूयॉर्क से दूर भी एक दूसरी एजेंसी है, जिसे समर्थन मिलता है और फंडिंग प्राप्त होती है। यह इस्राइल है, जिसे अमेरिका का वरदहस्त प्राप्त है। मुझे ऐसा लगा कि अगर हिलेरी क्लिंटन ने अपनी ही टिप्पणियों को ध्यान से सुना होता तो शायद उनमें आत्मचिंतन की क्षमता अधिक होती। मुझे इस बात पर संदेह है कि वाशिंगटन में एक लंबा समय गुजारने के बाद वह अपनी सरकार को किसी भी चीज के लिए दोषी ठहराएंगी। वर्तमान विवाद से पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों और सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में इस्राइल को अपनी मौन सहमति दी है। पूरे पश्चिमी तट पर के आस-पास हो रहे यहूदियों के विस्तार की वजह से वाशिंगटन को कभी हल्की फटकार तो लगती है, लेकिन कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वह डेमोक्रेटिक प्रशासन हो या फिर रिपब्लिक, दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने इस्राइली सेना के समर्थन से फलीस्तीन की जमीन पर बसने वाले यहूदियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। दशकों से बस रहे इन यहूदियों ने फलीस्तीन राज्य के निर्माण को असंभव बना दिया। इसमें अमेरिका और इस्राइल, दोनों बराबर के दोषी हैं। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के आपराधिक उल्लंघनों में इस्राइल का प्रमुख भागीदार रहा है। हालांकि इसमें अन्य देश भी सहयोगी हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं और सही मायनों में देखा जाए तो हम भी कम दोषी नहीं हैं। हम हमास द्वारा इस्राइल पर किए गए हमलों की पहली बरसी तो मनाते हैं, पर जब हम इस्राइल के हाथों मारे जा रहे निर्दोष फलीस्तीनियों को लेकर विचार करते हैं तो हमें अमेरिकियों की तुलना में कुछ हद तक अधिक आत्मजागरूक और आत्मआलोचनात्मक होना चाहिए। हमें अपनी सरकार को भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि उसने कम से कम दो तरीकों से इस्राइली अभियान को सहायता प्रदान की। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम और इस्राइल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के आह्वान वाले प्रस्तावों का समर्थन न करना और दूसरा, युद्ध की वजह से खस्ताहाल हुई इस्राइल की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रवासी मजदूरों को भेजना।

आज का इतिहास

1951 पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लीकायत अली खान की हत्या की गई।
1959 बोस्टन पैट्रियट्स एएफएल अमेरिकन फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई।
1964 चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया।
1968 संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद का विरोध करने के लिए, अफ्रीकी अमेरिकनथलेट्स टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने मेक्सिको सिटी समर ओलंपिक में एक पदक समारोह में ब्लैक पावर को सलामी दी।
1975 पूर्वी टेलोर के आक्रमण के लिए इंडोनेशियाई विशेष बल के सिपाही द्वारा बालिबो के इंटहे शहर स्थित ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन नेटवर्क के पांच पत्रकारों को मार दिया गया था।
1978 करोल, पोलैंड के कार्डिनल करोल जोजेफ वोज्टीला, 16 वीं शताब्दी के बाद से पहले स्लाव देश से पहली बार गैर-इतालवी पोप बन गए।
1982 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
1984 बिल आईटीवी पर शुरू हुआ, अंततः ब्रिटिश टेलीविजन इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली पुलिस प्रक्रियात्मक बन गया।
1995 द नेशन ऑफ इस्लाम के लुइस फ़ारखान ने वाशिंगटन, डीसी में मिलियन अमेरिकी शासक को बुलाया, जो अफ्रीकी अमेरिकी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक बीमारियों के खिलाफ आत्म-सहायता और आत्म-रक्षा में एकजुट होने के प्रयास में था।
1996 1998 फीफा विश्व कप क्वालीफिकेशन मैचबेटन ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका को देखने के लिए ग्वाटेमाला सिटी के एस्तियो मटेओ फ्लोरेस में प्रशंसकों की अत्यधिक संख्या में कम से कम 83 लोगों की मौत हो गई और 140 से अधिक घायल हो गए।
2006 रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संख्या 118 के साथ एक नए रासायनिक तत्व की खोज को प्रकट किया, जिसे अस्थायी रूप से यूनोक्टियम कहा जाता है।

कांग्रेस को सोनिया गांधी की आवश्यकता

प्रभु चावला

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का दृढ़ विश्वास है कि केवल सोनिया ही पार्टी को एकजुट रख सकती हैं और सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम कर सकती हैं। वे सबसे लंबे समय (डेढ़ दशक से अधिक) तक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। उनके कार्यकाल में ही पार्टी ने लगातार दो बार केंद्र में सत्ता हासिल की। साल 2004 में पार्टी को सिर्फ 145 सीटें मिली थीं। उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया और उनसे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद की जा रही थी।

यह एक ऐसा अपवाद है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कांग्रेस को जीत से ज्यादा हार में प्रचार मिलता है। पिछले हफ्ते चुनावी जानकारों की भविष्यवाणी के विपरीत जब कांग्रेस हरियाणा में हारी, तो ज्ञानियों ने यह समझाने के लिए कि वोट शेयर में वृद्धि का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की अपनी थकी हुई कहानी को फिर दोहराया। हमेशा की तरह स्थानीय नेतृत्व को ही खलनायक बनाया गया, राष्ट्रीय नेताओं को नहीं। पार्टी के जुझारू सेनापति राहुल गांधी का मजाक जरूर उड़ाया गया। गुटबाजी, उम्मीदवार चयन में गलती, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी, सामूहिक नेतृत्व का अभाव और जातिगत ध्रुवीकरण जैसे सामान्य बहाने इस बात के स्पष्टीकरण के रूप में दिये गये कि क्यों एक सुनिश्चित जीत अपमानजनक हार में बदल गयी। पार्टी के एक वर्ग ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी ठहराया, तो अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी और उनके करीबियों पर भीतरघात का आरोप लगाया। यह लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा से कहीं ज्यादा कांग्रेस बनाम कांग्रेस थी। यह स्थानीय जाति और समुदाय के सरदारों के बीच खुली लड़ाई थी। गांधी परिवार के अगुआई वाले केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें एक साथ लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बदला लेने पर उतारू असंतुष्टों पर लगाम लगाने में असमर्थता के कारण पार्टी ने एक दर्जन से अधिक सीटें खो दीं।

इस हार को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हरियाणा में इसलिए हार हुई क्योंकि गांधी परिवार सत्ता के लालची विद्रोहियों को रोकने में पूरी तरह विफल रहा। राहुल ने पोस्टकार्ड राजनीति की, मंच पर हर कोई उनके साथ एक खूबसूरत तस्वीर खिंचवा रहा था, लेकिन सामूहिक सौहार्द की कोई फोटो नहीं थी। प्रियंका गांधी, जो एक महत्वपूर्ण महासचिव हैं, की उपस्थिति पूरे प्रचार अभियान के दौरान न्यूनतम रही। दोष पार्टी की

जटिल नियंत्रण एवं कमान प्रणाली में है। भाजपा के विपरीत, जिसे सीधे मोदी-शाह की टर्बो टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कांग्रेस में एक संरचित पदानुक्रमिक तंत्र का अभाव है क्योंकि गांधी परिवार इसे एक निजी इकाई के रूप में मानता है। अपने हाथों में रिमोट कंट्रोल के साथ वे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तक की नियुक्ति करते रहे हैं। चूंकि पार्टी के चुनाव बहुत कम होते हैं, इसलिए या तो गांधी परिवार के अनुयायी या उनके गुट के चुने हुए लोग ही राज्यों में प्रमुख के तौर पर थोपे जाते हैं। इस अति-केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया के कारण कांग्रेस न केवल आम चुनाव, बल्कि कई राज्यों में भी चुनाव हार गयी। साल 2005 तक आधे से अधिक राज्यों में शासन करने वाली पार्टी अब सिर्फ तीन राज्यों में शासन कर रही है। उत्तर में केवल हिमाचल प्रदेश ही बचा है। गांधी के नेतृत्व में पार्टी का भौगोलिक दायरा बहुत कम हो गया है। फिर भी, कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।

कांग्रेस का विरोधाभास यह है कि वह अपनी गहरी ग्रामीण जड़ों और गांधी परिवार के साथ जुड़े रहने के कारण ही अस्तित्व में है। उनके वफादार संगठन को नियंत्रित करते हैं। सोनिया गांधी एकजुटता लाती हैं तथा राहुल योद्धा और मुखर प्रवक्ता हैं। जब वे पहले उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष के रूप में पार्टी को संभालने में विफल रहे, तो सोनिया ने पार्टी के दलित चेहरे और पुराने योद्धा मल्लिकार्जुन खरगे को चुना। कांग्रेस नेताओं को संभालने में उनकी निपुणता और वरिष्ठ होने के नाते अनुभवी विपक्षी नेताओं से जुड़ने की क्षमता के कारण उन्हें पदोन्नत किया गया, जो राहुल के साथ उतने सहज नहीं होते। राहुल की दो यात्राओं के बाद यह स्थिति बदल गयी है। वे लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी को शर्मिंदा करते हैं। इस बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं, लेकिन पिछले एक दशक में इसने ज्यादा राज्य खो दिये क्योंकि राहुल ने पार्टी के भविष्य के रूप में खुद को स्थापित करने के बजाय अपने वफादारों का समूह बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन तक पहुंच की मुश्किल और उनके अभिजनवाद ने कांग्रेस का नुकसान किया है। अब इसके पास संसद और विधानसभाओं में 25 प्रतिशत से भी कम सीटें हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का दृढ़ विश्वास है कि केवल सोनिया ही पार्टी को एकजुट रख सकती हैं और सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम कर सकती हैं। वे सबसे लंबे समय (डेढ़ दशक से अधिक) तक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। उनके कार्यकाल में ही पार्टी ने लगातार दो बार केंद्र में सत्ता हासिल की। साल 2004 में पार्टी को सिर्फ 145 सीटें मिली थीं। उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया और उनसे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उन्होंने इसके बजाय मनमोहन सिंह को चुना। उनकी अंतरात्मा की आवाज ने उन बाहरी आवाजों को दबा दिया, जो उनकी चापलूसी कर रही थीं। उस समय यह एक कहावत बन गयी कि पद से ज्यादा सिद्धांत को तरजीह दी गयी।

सोनिया गांधी का उद्देश्य विपक्ष को एकजुट करना था। उन्होंने यूपीए में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी शरद पवार को स्वीकार किया, जिन्होंने उनके विदेशी मूल का हवाला देते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति नामित करने की मुलायम सिंह यादव की अपील को स्वीकार किया। एकता के लिए उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यादव ने उन्हें तब प्रधानमंत्री बनने से रोका था, जब 1998 में वाजपेयी ने सिर्फ एक वोट से विश्वास मत खो दिया था। राहुल को आगे बढ़ाने के बाद वे पिछले कुछ सालों से वही भूमिका निभाने से बचती रही हैं। हरियाणा में अप्रत्याशित हार ने उन्हें फिर से केंद्रीय मंच पर ला दिया है। चूंकि कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वे उनसे फिर से सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके प्रतिद्वंद्वी डीके शिवकुमार के झगड़े में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में गुटों में सुलह हो। वे सफल इंडिया गठबंधन के निर्माण के पीछे थीं, जिसने मई में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया। उनके वफादारों को यकीन है कि सिर्फ वे ही पार्टी की ताकत को फिर से बहाल कर सकती हैं। अगले 12 महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भविष्य की भूमिका तय करेगा।

धर्म को न बनाएं राजनीति का हथियार

विश्वनाथ सचदेव

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आशा प्रकट कि थी कि ''धर्म को राजनीति से दूर रखा जाएगा पर ऐसा होता नहीं। चुनाव-दर-चुनाव हमने धर्म को राजनीति का हथियार बनाए जाते देखा है। कभी किसी पर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का आरोप लगाया जाता है और कभी किसी को बहुसंख्यकों को गोलबंद करने का आरोप झेलना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों ही आरोप बेबुनियाद नहीं हैं। जब हमने अपना संविधान बनाया था तो उसमें इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि धर्म हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा, शासन किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपने विश्वास और आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन करने की आजादी और अधिकार दिया है। यही नहीं, हमारा संविधान यह भी कहता है कि किसी को भी अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की आजादी है। संविधान यह भी कहता है कि अपने धर्म की बात करते हुए किसी को दूसरे धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है। संविधान की इन बातों को हमारे राजनीतिक दल और राजनेता अक्सर दोहराते अवश्य हैं, पर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म का दुरुपयोग करने से भी नहीं कतराते। दुर्भाग्य और चिंता की बात यह है कि हमारे भारत में धार्मिक सहिष्णुता के सारे दावों के बावजूद 'राजनीति का धर्मकरण' हो रहा है। अर्से से हम देख रहे हैं कि वैयक्तिक विश्वास, ईश्वर और राजनीति के बीच की रेखाएं मिटती जा रही हैं. कभी बहुसंख्यकों के हाथों में 'धर्म खतरे में है' का नारा थमा दिया जाता है और कभी अल्पसंख्यकों को यह आगाह किया जाता है कि उनके हकों को छीना जा रहा है। अनेक धर्मों का देश होना हमारी एक सच्चाई है, और हर धर्म का सम्मान होना हमारे अस्तित्व की आवश्यकता। हिंदू और मुसलमान, या जैन या सिख या बौद्ध, सब इस देश के नागरिक हैं, हमारा संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है। हम भले ही किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हों, हम सब भारतीय हैं. इस देश पर हम सबका अधिकार है। और हम सबका कर्तव्य है कि देश की एकता को बनाए रखने के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ जागरूक रहें। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज देश में ऐसे तत्व और ऐसी सोच लगातार सक्रिय और ताकतवर हो रहे हैं जो हमारी भारतीयता को सीमित बनाते हैं। आसेतु-हिमालय यह भारत हम सबका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश में रहने वाले हर भारतीय को हिंदू बताया था। उनकी इस बात को थोड़े व्यापक संदर्भ में देखने-समझने की आवश्यकता है। हम चाहे स्वयं को हिंदू कहें या भारतीय, हमें समझना यह है कि बांटने वाली ताकत कभी भी किसी धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती। धर्म हमें जोड़ने वाली शक्ति है। आज आवश्यकता धर्म को बांटने वाली ताकत के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिशों को विफल बनाने की है। सांस्कृतिक हिंदू को राजनीतिक हिंदू समझना-समझाना कुल मिलाकर भारतीयता को ही कमजोर बनाएगा। हमारी आवश्यकता इस भारतीयता को मजबूत बनाने, बनाए रखने की है।

हिंसा से नहीं विकास से होगा नक्सलवाद का खात्मा

योगेन्द्र योगी

लोकतंत्र का रास्ता छोड़ कर हथियारों के बल पर क्रांति लाने का ख्वाब पाले नक्सलियों को इसकी कीमत अपने खून से लगातार चुकानी पड़ रही है। हथियारों के बल पर हिंसा के जरिए दहशत फैलाने वाले नक्सलियों को यह समझ में नहीं आया कि क्रांति वहां होती है, जहां राजशाही या तानाशाही का शासन हो। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांग मनवाई जा सकती है। इसका सीधा रास्ता है चुनाव की प्रक्रिया के जरिए अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुनना और कानून बनवाना।

इसके विपरीत हथियारों के बलबूते हिंसा के रास्ते पर चलने का नतीजा खून-खराबे के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। नक्सली प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की लगातार कसती जा रही घेराबंदी में बड़ी तादाद में युवा नक्सलियों की जान जा रही है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर-दंतेवाड़ा सीमा के पास सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के साथ जंगल में हुई मुठभेड़ में 32 माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अब तक ऐसी सैंकड़ों मुठभेड़ों में भटके हुए युवा हजारों की संख्या में अपनी जान गंवा चुके हैं। सुरक्षा बलों की संख्या और मजबूती के सामने नक्सली कहीं नहीं टिक सकते। यह जानते हुए भी कि नक्सलवाद एक हारी हुई लड़ाई है, गुमराह नक्सली जान देने पर आमादा हैं।

इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है, बदलाव के लिए जिन युवाओं के हाथों में कलम, कम्प्यूटर या ऐसे ही समाज और राष्ट्र निर्माण के उपकरण हो सकते हैं, उनके हाथों में हथियार हैं। इसमें भी उन्हें कहीं चैन-सुकून नहीं है। पुलिस की गोली जंगलों में कब उनका काम तमाम कर दे, इसका डर उन्हें दिन-रात सताता रहता है। परिवार और समाज से दूर यायावरों की तरह जंगलों में भटकने वाले नक्सलियों पर हर वक्त मौत का साया मंडराता रहता है। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए। देश में बदलाव लाने के लिए नक्सलियों के हिंसात्मक आंदोलन को भी 6 दशक से ज्यादा का समय हो गया। नक्सलियों का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है।

नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के एक छोटे से

गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने सरकार के खिलाफ 1967 में एक मुहिम छेड़ी थी। देखते ही देखते यह एक आंदोलन बन गया और चिंगारी फैलने लगी। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने खुद सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। यह विद्रोह उन किसानों का था, जो जमींदारों के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जंगलों में पैतृक अधिकारों से वंचित आदिवासियों ने सरकारी तंत्र के जुल्म-सितम से तंग आकर कोई विकल्प नहीं देख कर नक्सली विचारधारा का दामन थामा।

राज्यों की सरकार ने दशकों तक इन इलाकों में विकास को तरजीह नहीं दी। इससे नक्सलियों के कुप्रचार का रास्ता और भी आसान हो गया। यही वजह रही कि पश्चिमी बंगाल से शुरू हुआ नक्सलवाद सीमावर्ती राज्यों में फैलता चला गया। बीते दशकों के दौरान नक्सलियों और सुरक्षाबलों को भारी जनहानि उठानी पड़ी। नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में विकास कार्य ठप्प पड़ गए। इसका फायदा उठा कर कट्टर नक्सलियों को युवाओं को बहकाने का मौका मिल गया।

नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों ने दो स्तरीय नीति बनाई। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राहत पैकेज और हिंसा करने वालों के प्रति सख्ती की नीति अपनाई।

इसी के तहत राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया। इनके पुनर्वास की योजना को मंजूरी दी गई। विवाह करने के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया ताकि युवा हिंसा का रास्ता छोड़ कर परिवार-समाज के साथ सामान्य जीवन बिता सकें।

इसके अलावा केंद्र और राज्य संयुक्त तौर पर नक्सलियों से निपटने की रणनीति पर लगातार कार्यरत हैं। नक्सलियों के राहत पैकेज की रफ्तार बेशक धीमी हो, किन्तु इसका फायदा उठा कर अब तक बड़ी संख्या में युवा हथियार छोड़ कर सामान्य जीवन व्यतीत करने में सफल रहे हैं। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के दबाव के साथ जरूरत इस बात की है कि विकास की रफ्तार तेज की जाए। नक्सलवाद के जड़ सहित खात्मे के लिए दबाव और विकास की रणनीति जरूरी है। सच्चाई यह भी है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, वह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है।

नक्सल प्रभावित इलाके आज भी पानी, बिजली, स्कूल-अस्पताल और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछड़ेपन के ऐसे हालात नक्सलवाद के कुप्रचार का रास्ता आसान बनाते हैं। दशकों तक राज्यों में नक्सली हिंसा की मूल वजह भी विकास में पिछड़ापन रही है। इसके अलावा सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार और लालफीताशाही ने नक्सलवाद की आग में घी का काम किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास का आकर्षण नक्सलियों को हथियार डालने के लिए प्रेरित करेगा। देश के अन्य हिस्सों की तरह दुर्गम नक्सली इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करनी होगी। नक्सली क्षेत्रों में समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पैकेज को प्रचार माध्यमों के जरिए प्रभावी बनाना होगा। राहत पुनर्वास पैकेज की जानकारी नहीं होना भी नक्सलियों के मुख्यधारा में शामिल नहीं होने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। इन बाधाओं को हटा कर ही देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में अमन-चैन कायम किया जा सकता है।

क्या तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाएगा?

उत्तम गुप्ता

क्या ये कानून भारत के लाखों संघर्षरत किसानों और उपभोक्ताओं के सामने आने वाली गहरी समस्याओं को संबोधित करने का एक खोया हुआ अवसर था? हाल ही में, भाजपा के एक सांसद ने 3 राष्ट्रीय कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात कही। विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करते हुए, भाजपा के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि 'उनका बयान पार्टी के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है'। मोदी सरकार इन कानूनों को वापस लाने का इरादा नहीं रखती है।

सितंबर 2020 में लागू किए गए इन कानूनों में सबसे दूरगामी कानून किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 था। इसने केंद्र को अंतर-राज्य व्यापार को विनियमित करने की अनुमति दी, जिससे किसान या व्यापारी को व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता मिली, जबकि व्यापारियों को देश में कहीं भी, यहां तक कि निर्दिष्ट राज्य ए.पी.एम.सी. (कृषि उपज बाजार समिति) के बाहर भी किसानों से सीधे निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं को खरीदने की अनुमति मिली। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020। इसने किसानों को प्रोसैसर, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं आदि के साथ 'निष्पक्ष' और 'पारदर्शी' तरीके से जुडने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 था। इसने दालों, अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज और आलू को इस पुराने कानून के दायरे से बाहर कर दिया। इन कानूनों के लागू होने से लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए जो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक ही सीमित थे।

जनवरी 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और गहन समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। 3 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। इस बीच, किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा।

19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निरस्त करने की घोषणा की।

लेकिन, सबसे पहले, हमें यह पूछना होगा कि कृषि उपज के विपणन पर मौजूदा कानून किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान की व्यापक रूप से बताई गई दुर्दशा सब कुछ बयां कर देती है। पिछले साल, उसे सोलापुर मार्केट यार्ड में एक व्यापारी को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 512 किलोग्राम प्याज बेचने पर मात्र 2.49 रुपए मिले, कुल बिक्री मूल्य 512 रुपए था; श्रम, तौल, परिवहन और अन्य शुल्कों को घटाने के बाद 509.5 रुपए की कुल राशि हुई, जो 2.5 रुपए थी। स्पष्ट है, यह लाभ नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए, हमें इसमें से 512 किलोग्राम प्याज के उत्पादन की लागत घटानी होगी जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर होने वाले खर्च शामिल हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी उपज केवल राज्य ए.पी.एम.सी. अधिनियम के तहत 'निर्दिष्ट' मंडी में ही बेच सकता है। मंडी में, कमीशन एजैंटों (वे उपज की नीलामी और डिलीवरी की व्यवस्था करते हैं)के लिए स्थानीय शब्द और लाइसैंस प्राप्त व्यापारी/खरीदार का बोलबाला है। ये दोनों कम कीमत देकर, अस्वीकार करके, कम तोल करके, भुगतान में देरी करके उसका भरपूर शोषण करते हैं। ए.पी.एम.सी. मंडियां किसानों द्वारा बेची जाने वाली मात्रा का केवल एक अंश ही संभाल सकती हैं। इसलिए, उनमें से अधिकांश को निजी स्थानीय बाजारों में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इन बाजारों में, वे अपनी उपज को औने-पौने दामों पर व्यापारियों को बेच देते हैं। बाद वाले को भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है (कई मामलों में, वे या उनके रिश्तेदार भी व्यापारियों के रूप में दिखावा करते हैं) और इसलिए, कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है।

यह सही है कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) जैसी राज्य एजैंसियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए आवश्यक फसलों की मंडियों से खरीद करती हैं। वे केंद्र द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर खरीदारी करती हैं। लेकिन उनकी खरीद सीमित है। धान और गेहूं को छोड़कर, जहां एजैंसियां किसानों की उपज का केवल 30 प्रतिशत ही खरीदती हैं, अन्य सभी फसलों के लिए उनकी खरीद नगण्य है। फिर भी केवल 6 प्रतिशत किसान जिनमें से अधिकतर बड़े जोत वाले अमीर हैं , सरकारी खरीद का लाभ पाते हैं।

संक्षेप में, मौजूदा समय में ए.पी.एम.सी. कानूनों के तहत, अधिकांश गरीब किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वे घोर गरीबी में जीने को मजबूर हैं और भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसके कारण आत्महत्याएं भी हो रही हैं। एन.एफ.एस.ए. के तहत 820 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन मिल रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपनी जरूरतों को बाजार से खरीदते हैं; यहां तक कि एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थी भी गेहूं/चावल के अलावा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार पर निर्भर हैं। किसानों को बेचने के लिए और उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए और अधिक विकल्प देना है। यही वह है जो तीनों कानूनों ने करने की कोशिश की है। इन कानूनों ने ए.पी.एम.सी. मंडियों को परेशान किए बिना सभी गैर-ए.पी.एम.सी. प्लेटफार्मों जैसे निजी व्यापारियों, प्रोसैसर, एग्रीगेटर, निर्यातकों आदि पर बिक्री को वैध बनाया।

विधानसभा चुनाव के परिणामों में निहित संदेश

बलबीर पुंज

बीते 8 अक्तूबर को हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के आए नतीजे अपने भीतर 3 स्पष्ट संदेशों को समेटे हुए हैं। पहला तमाम शंकाओं के बावजूद भारत का लोकतंत्र अधिक मजबूत होकर उभरा है। दूसरा स्वयं-भू चुनाव विश्लेषकों का अनुमान वैज्ञानिक आधार पर कम, तीर-तुक्का ज्यादा दिखता है। तीसरा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए नरेटिव से एक सीमित सीमा तक ही राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है और मतदाता जमीन पर हुए काम के साथ सकारात्मक परिवर्तन को ही ठोस मापदंड मानते हैं। हरियाणा में 10 वर्षीय सत्ताविरोधी लहर के बीच पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना ऐतिहासिक है। नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आए हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणामों को देखा जाए, तो यहां मतदाता ने किसी भी राजनीतिक दल को कभी लगातार 3 बार सत्ता नहीं सौंपी है। भाजपा को वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत से अधिक मतों के साथ 47 सीटें मिली थीं, जो 2019 के चुनाव में पहले से अधिक 36.5 प्रतिशत मत हासिल करने के बाद भी घटकर 40 सीट हो गई थी। तब भाजपा ने दुष्यंत चौटाला की नवगठित जननायक जनता पार्टी (जे.जे.पी.) के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार न केवल भाजपा का मत प्रतिशत बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत पहुंच गया, बल्कि सीटें भी बढ़कर 48 हो गईं। सत्ताविरोधी लहर के बीच यह उसका हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले 2 चुनावों की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही सुधरा हो, परंतु वह भाजपा को परास्त करने के लिए नाकाफी रहा। इसका कारण भी स्पष्ट है। कांग्रेस की ओर से चुनाव अभियान में लगातार प्रचार किया गया था कि भाजपा 'जवान-नौजवान-किसान-पहलवान' के खिलाफ है। वर्ष 2020-21 से हुए तथाकथित कृषक आंदोलनों को आधार बनाकर कांग्रेस ने भाजपा को किसान-विरोधी बताने का प्रयास किया था। पहली बात उस आंदोलन में पंजाब के किसानों की भागीदारी अधिक मुखर थी, जिसे एकाएक भारतविरोधी शक्तियों ने अपने एजैंडे को पूरा करने का उपक्रम बना दिया था। सच तो यह है कि मोदी सरकार ने कृषि उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक हरियाणा सहित देशभर के खेतिहरों को 3.45 लाख करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मोदी सरकार 'किसान मानधन', 'किसान फसल बीमा', 'पी.एम. राष्ट्रीय कृषि विकास' और 'कृषि उन्नति' रूपी कई योजनाएं धरातल पर बिना किसी भ्रष्टाचार के चला रही है। मोदी सरकार जहां 23 तरह की फसलों (अनाज-दाल-तिलहन सहित) पर न्यूनतम समर्थन (एम.एस.पी.) मूल्य दे रही है, तो हरियाणा में भाजपा ने 24 फसलों पर एम.एस.पी. देने का वायदा किया है। भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत और भारतीय सेना में उसका योगदान 11 प्रतिशत है। इसलिए संकीर्ण चुनावी लाभ के लिए देश के सामरिक हित से जुड़ी 'अग्निवीर योजना' का भी कांग्रेस दानवीकरण कर रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। बीते 10 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में असीम प्रगति की है। 'आत्मनिर्भर भारत' की पृष्ठभूमि में देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो 2014 में बमुश्किल 500-600 करोड़ रुपए हुआ करता था। स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना पर कुप्रचार के साथ कांग्रेस की जातिवाद प्रेरित राजनीति, भारतीय उद्योग प्रतिभा के अपमान और पहलवानों के माध्यम से भारतीय खिलाडियों के मनोबल पर प्रहार को हरियाणा के मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया। हरियाणा चुनाव के नतीजों को मानने से इंकार करना और चुनाव प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाने का प्रयास, असल में कांग्रेस की कुंठा, अहंकार, आत्मघाती चरित्र, असहमति के प्रति असहिष्णुता और जन-सराकारों से कटाव को ही दर्शाता है। चुनाव से पहले और मतदान के तुरंत बाद हुए सर्वेक्षणों ('एग्जिट पोल' सहित) में दावा किया गया था कि हरियाणा में कांग्रेस एक दशक बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। लगभग सभी सर्वे ने कांग्रेस के 50 या उससे अधिक सीटें का अनुमान जताया था। परंतु इस बार भी 'एग्जिट पोल' इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के भांति औंधे मुंह गिर गए। तब सभी टी.वी. चुनावी सर्वेक्षणों ने भाजपा के अपने बलबूते लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की भविष्यवाणी की थी। नतीजे क्या आए थे, सुधि पाठक इससे अवगत हैं। क्या लगातार विफलता के बाद 'एग्जिट पोल' बंद हो जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। वर्ष 2019 में धारा 370-35ए हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा को 29 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती की पी.डी.पी. पिछले चुनाव की तुलना में 28 से सीधे 3 सीटों पर सिमट गई, तो निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने 10 सीटों पर कब्जा कर लिया। भाजपा को इस बार भी जम्मू में ही जीत मिली है। उसने सभी सीटें, 43 सीट वाले जम्मू क्षेत्र में जीती हैं, जबकि उसे कश्मीर में पिछली बार की तरह एक भी सीट नहीं मिली। मतदान का बहिष्कार करना तो दूर, कानून व्यवस्था की स्थिति भी कहीं पैदा नहीं हुई। कश्मीरी मतदाताओं द्वारा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना, भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनके बढ़ते भरोसे और घाटी में अशांति-अविश्वास बढ़ाने के लिए तत्पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का सूचक है।

क्या आप अपने नए घर को पेंट करवाने का सोच रहे हैं?

क्या आप अपने नए घर को पेंट करवाने का सोच रहे हैं? या अपने पुराने आशियाने को ही नई रंगत देकर नया लुक देना चाहते हैं? यदि हां, तो आपकी घर की दीवारों को पेंट करवाने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि किन रंगों से महकेगा आपका आशियाना। घर की साज-सज्जा एवं रंग-रोगन के लिए दिशा के अनुसार चुनें इन 5 समृद्धिदायक रंगों को, और पाएं वर्ष भर खुशहाली व सुख-समृद्धि। जानें कैसे करें रंगों का चुनाव...

हिन्दू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के लिए कई दिन पहले से घर में साफ-सफाई और रंग-रोगन का दौर शुरू हो जाता है। घर में सुख शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहे इसलिए कई लोग घर की साज-सज्जा व रंगाई के लिए वास्तु और फेंगशुई के टिप्स भी आजमाते हैं।

- घर का बैठक कक्ष सबसे अहम होता है, इसलिए यहां की दीवारों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यहां पर भूरा, गुलाबी, सफेद या क्रीम कलर सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर इन रंगों के परदे या तकिए कवर का इस्तेमाल भी शुभ फल देता है।
- भोजन कक्ष को रंगवाते समय आसमानी, हल्का हरा व गुलाबी रंग करवा सकते हैं। इससे हमेशा ऊर्जा व ताजगी का संचार होता है और सकारात्मकता बनी रहती है।
- रसोई घर में सफेद रंग हमेशा अच्छा माना जाता है। हांलाकि यह गंदा भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर सफाई बनाएं रखें तो यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है।
- बाथरूम या शौचालय के लिए हल्का गुलाबी या फिर सफेद रंग ही सबसे बेहतर होते हैं। खास तौर से बाथरूम में गुलाबी रंग का प्रयोग ताजगी बनाए रखता है और आप आंतरिक खुशी महसूस करते हैं।
- शयन कक्ष भी काफी महत्वपूर्ण होता है, यहां पर भी आप हल्का हरा, आसमानी, गुलाबी जैसे रंगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें देखकर मन हमेशा प्रसन्न रहे। इससे आपके रिश्तों में भी मधुरता आती है।
- पीला रंग सुकून व रोशनी देने वाला रंग होता है। घर के ड्राइंग रूम, ऑफिस आदि की दीवारों पर यदि आप पीला रंग करवाते हैं तो वास्तु के अनुसार यह शुभ होता है।
- अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको अपने कमरे की उत्तरी दीवार पर हरा रंग करना चाहिए।
- आसमानी रंग जल तत्व को इंगित करता है। घर की उत्तरी दीवार को इस रंग से रंगवाना चाहिए।
- घर के खिड़की दरवाजे हमेशा गहरे रंगों से रंगवाएं। बेहतर होगा कि आप इन्हें डार्क ब्राउन रंग से रंगवाएं।
- जहां तक संभव हो सके घर को रंगवाने हेतु हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करें।

क्या है बच्चों की मालिश का परफेक्ट तरीका

कोरोनाकाल में घर से लेकर ऑफिस तक के काम का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में रात में बच्चों को सुलाने में मशक्कत करनी पड़े तो मन में खीज पैदा होना लाजिमी है। अगर काफी देर तक घुमाने-टहलाने और लोरी सुनाने के बाद भी आपके लाडले की आंखों में नींद नहीं भरती तो परेशान मत होइए। लंदन के मशहूर मसाज विशेषज्ञ ने मालिश की ऐसी विधि सुझाई है, जिससे आपका बच्चा मिनटों में नींद के आगोश में चला जाएगा।

मां-बाप की मशक्कत

- मां-बाप को बच्चे के जन्म के शुरुआती एक साल में 04 घंटे 44 मिनट की औसत नींद मिलती है
- 50 रातों की नींद गंवाने के बराबर है यह आंकड़ा, स्वस्थ वयस्कों को आठ घंटे रोजाना सोना चाहिए
- 54 मिनट औसतन रोजाना बच्चे को सुलाने में लगते हैं, तीन बार औसतन रात में उठता है बच्चा
- 02 मील रोजाना चलना-फिरना होता है मां-बाप का बच्चे को बहलाने, फुसलाने, सुलाने की प्रक्रिया में।

पूरे शरीर में लगाएं तेल

- सरसों, नारियल या जैतून का तेल लें, सिर से लेकर पांव तक हल्के हाथों से हर एक अंग में लगाएं
- अब ऊपर से नीचे की तरफ धीमी गति से हाथ फिराते हुए 10 से 15 मिनट तक बच्चे की मालिश करें

बातों में उलझाए रखें

- साज करते समय चेहरे पर मुस्कराहट जरूर बनाए रखें
- बच्चे से धीमे स्वर और तुतलाती भाषा में प्यार-भरी बातें करें
- तेज मालिश करने से बचें, बच्चा रोए तो उस पर चिल्लाएं नहीं

खास जगहों पर मसाज जरूरी

- नाक का ऊपरी हिस्सा - दोनों भौहों के बीच नाक के शुरुआती हिस्से पर अंगूठे और तर्जनी उंगली से हल्की मालिश करें। बच्चे का मन शांत करने में मदद मिलती है।
- हथेली - दोनों हथेलियों पर धीमे-धीमे से हाथ फिराएं। पांचों उंगलियों के बीच के स्थान पर कम से कम 30 सेकेंड तक हल्की मसाज दें। दांत दर्द की समस्या दूर होगी।
- पेट - दर्द, गैस, कब्ज की समस्या से राहत दिलाने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पेट पर बाईं से दाईं ओर गोलाई में हल्के हाथ से पांच मिनट तक मसाज करें।
- पंजे - अंत में बच्चे के दोनों पैरों के पंजे अपने हाथों में लें। अब पंजे के बीच के हिस्से को अंगुठे से 10 से 15 सेकेंड के लिए दबाएं। उसका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाएगा।

मन शांत करने में मददगार

- हल्के हाथों की मालिश लव हार्मोन 'ऑक्सिटोसिन' का स्तर बढ़ाने के साथ ही स्ट्रेस हार्मोन 'कॉर्टिसोल' का उत्पादन घटाने में कारगर
- इससे बच्चे के मस्तिष्क में मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा के शांत पड़ने से तन-मन को सुकून महसूस होता है, शरीर में सुस्ती भी छाती है

गुनगुना दूध पिलाना भी फायदेमंद

- सोने-जगने का समय तय करें, उसे रोज अमल में भी लाएं
- रात में बिस्तर पर आने के बाद बच्चे को गुनगुना दूध पिलाएं
- कमरा हल्का ठंडा रखें, मुलायम गद्दे पर सुलाएं, लोरी सुनाएं

बढ़ते बचपन के साथ व्यावहारिक समझ विकसित करती हैं बेटियां

बेटियां कैसे अपने बढ़ते बचपन के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों और व्यावहारिक समझ को विकसित करती हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहण है एक पिता के द्वारा लिखा गया ये लेख।

सिर्फ ग्यारह साल की है मेरी बिटिया। पांचवी में पढ़ती है। यूनिटरी फैमिली में एक बच्चे को क्या-क्या झेलना पड़ता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है वह। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं। हमने खुद से जद्दोजहद करते, बिना किसी के सपोर्ट के जीवन जीना सीखा है और परिवार के बुजुर्गों की परवरिश से दूर मेरी बेटी ने भी खुद ही सबकुछ सीख लिया। जब वह डेढ़ साल की थी, तभी से मछली का कांटा निकाल कर खुद खाती थी। हम कामकाज में व्यस्त रहते और वह कांटा निकालने की तरकीब ढूंढती रहती। यह उसने अंतत: सीख ही लिया। किसी दिन उसकी मां को एक्जाम ड्यूटी के लिए रविवार के दिन सुबह आठ बजे ही निकलना होता। कभी-कभी मुझे भी कालेज में कक्षाएं लेने पत्नी के साथ ही आठ बजे निकलना होता है। उस वक्त बेटी की आंखों में यह सवाल होता है कि तुम दोनों शाम तक लौटोगे, तो मैं दिनभर क्या करूंगी, अकेली कैसे रहूंगी। पर वह बोलती कुछ नहीं।

उसकी आंखों में हठात एक सूनापन सा आता है और आकर चला जाता है। वह तपाक से कहती है। तुमलोग जाओ। दरवाजे में बाहर से ताला लगा देना। मैं अंदर से कुंडी बंद कर दूंगी और टीवी देखती रहूंगी। ऐसा कई बार हुआ है कि हम दोनों आठ-दस घंटे बाहर होते हैं और बेटी ने दिनभर टीवी देखते हुए, बाहर से ताला लगे बंद कमरे में खुद को अकेली बिताया है। जाते वक्त हम उसका खाना, बिस्किट वगैरह रख देते हैं। हिदायत देते हैं- बेटा आग के पास मत जाना, गैस मत खोलना। बिजली कट जाये, तो बिजली आने का इंतजार करना-माचिस मत जलाना। बेटी ठीक वैसा ही करती है। आज तक उसने वैसा ही किया है। यह सिलसिला पिछले चार-पांच सालों से चल रहा है। जब वह पांच-छह साल की थी, तब से। हम दिनभर अपने काम के साथ बेटी की चिंताओं में घुलते रहते हैं कि पता नहीं वह कैसी होगी। शाम को जब दरवाजे का ताला आकर खोलते हैं, तो कभी वह अपना होमवर्क कर रही होती है। उसने घर के अंदर, बंद ताले में खुद को सेफ रखने के लिए सभी उपाय सीख लिए हैं। जैसे ही वह बाहर कोई आहट सुनती है, टीवी धीमा कर देती है। कोई आवाज नहीं निकालती। वह धीरे-धीरे बड़ी हो रही है। फिजिकली। मेंटली वह समय से पहले ही बड़ी हो गयी है। यह सब उसे कुछ हमने सिखाया है, तो कुछ परिस्थितियों ने। अपनी कई मुश्किलें वह अपनी मां के साथ शेयर करती है, तो लगता है कि इसने अपना बचपना थोड़ा खोया, थोड़ा झटका है। महज ग्यारह साल की उम्र में उसे परिस्थितियों ने परिपक्व बना दिया है। पर, वह अकेली बिटिया है। उसे जीना इसी समाज में है।

...तो रिश्ता हो जाएगा मजबूत

दुनिया में रिश्ते के बिना प्यार का अहसास ही नहीं हो सकता। रिश्ता चाहे कोई भी हो खास होता है। इसे निभाने के लिए शुरुआत भी अलग तरीके की होना चाहिए। फिर चाहे वो दोस्ती हो या फिर रिश्तेदारी।

खुशियों का अहसास अपनो से ही होता है। इसे हमेशा के लिए गहरा करने के लिए कुछ खास बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आने वाला हर पल हसीन रहे। अगर किसी कारण रिश्तों में गलतफहमियां आ भी जाए तो एक दूसरे पर यकीन इतना गहरा हो कि कोई दूसरा आपमें अपनी जगह बना न सके। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है ताकि प्यार से संजो कर रखा गया यह रिश्ता जिंदगी की जरूरत बन जाए।

एक दूसरे को जानना जरूरी

आप किसी से प्यार करते हैं तो इसके लिए एक बात को जान लेना बहुत जरूरी है आपको उसकी आदतों के बारे में जानना होगा। इससे आप खुद को और अपने बढ़ते रिलेशनशिप को कुछ समय दे पाएंगे। जो भविष्य में आपके लिए परेशानी नहीं बनेगा।

रिलेशनशिप से बनें पहचान

दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्ती इस तरह की हो जो आपकी पहचान बनें। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोस्ती में खोते जा रहे हैं। यह बदलाव आपके लिए खतरनाक हो सकता है।

कभी शक भी जायज

जहां यकीन है वहां शक होना भी कभी कभी जायज होता है। पार्टनर पर जरूरत से भी ज्यादा यकीन कर लेने से भी कई बार रिश्ता खराब होने का डर रहता है। थोड़ा बहुत शक करना या फिर पजेसिव होने से पार्टनर को भी पता चलता है कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं।

एक-दूसरे को दें वक्त

एक-दूसरे के साथ समय बिता कर उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। कई बार ज्यादा देर तक बनाई गई दूरी भी रिश्ते में खट्टास पैदा कर सकती है। ऐसे में समय की कमी के कारण अगर पार्टनर के साथ नराजगी है तो एक-दूसरे को समय जरूर दें। कहीं न कहीं आपके रिश्ते में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें एक- दूसरे के साथ समय बिताएं।

वॉर्डरोब में नए-पुराने कपड़ों को इस तरह से करें टिमअप और रखें वॉर्डरोब को अपडेट

हमसे से अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो समय की कमी के कारण अपने वॉर्डरोब पर ध्यान नहीं दें पाते। जिसके कारण वॉर्डरोब में नए-पुराने कपड़ों का ढ़ेर लग जाता है। वक्त है, कोरोना काल का जिसमें सोशल डिस्टेंसिग का हम सभी पालन कर रहे है। जिस वजह से हम अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिता रहे है। तो क्यों न इस समय का सही इस्तेमाल करते हुए अपने वॉर्डरोब को अपडेट किया जाएं। आइए जानते कुछ टिप्स-

- डार्क कलर के 1-2 पैंट्स अगर आपके वॉर्डरोब में हैं, तो नए लुक के लिए कुछ कलरफुल शॉर्ट कुर्ते खरीदें। कलमकारी, इकत या लखनवी चिकन के शॉर्ट कुर्ते अच्छे लगते है। साथ ही रूटीन में पहनें जानेवाले टॉप और पैंट स्टाइल को भी ब्रेक मिलता है।
- प्लेन टाइट टीशर्ट यदि आपके वॉर्डरोब में है तो इसको आप कलरफुल धोती पैंट के साथ आप टीमअप कर सकते है।
- यदि वॉर्डरोब में पुरानी प्रिंटेड सलवारों ने काफी जगह घेर रखी है, तो इनके उपर पहनने के लिए 1 से 2 कुर्ती खरीदें।
- यदि पेन्सिल जींस आपके पास हैंतो 1 से 2 फ्लोरल लॉन्ग लाइन शर्ट खरीदें।
- पुराने शॉर्टर्स अलनारी में है तो फिल नेक ब्लाउज टॉप या कॉन्ट्रास्ट बाइंजिंग नॉट टॉप खरीदें। नया टॉप पहनने पर पुराने शॉर्टर्स भी नए लुक में नजर आते है।
- अगर आपके पास कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट है, तो उसके साथ शॉर्ट कुर्ती, टीशर्ट या लॉन्ग कुर्ते भी पहने जा सकते है।
- ए लाइन फुल लेंथ स्कर्ट पहले से है, तो उसके साथ लॉन्ग कुर्ते पहनें, हील्स पहनें। इससे हाइट अच्छी दिखगी।
- शॉर्ट स्कर्ट के साथ जैगिंग्स पहनना ट्रेंडी लुक देगा। साथ में एक्सेसरी के तौर पर स्कार्फ भी लें।

वॉर्डरोब में इन बातों का रखें ख्याल

- पैंट, जींस के लिए मल्टीपर्पस 5 लेअर हैंगर का इस्तेमाल करें। यह वॉर्डरोब की जगब को कम घेरेगा और वॉर्डरोब संवरा दिखेगा।
- सॉक्स और अंडरगारमेंट्स आर्गेनाइजर भी वॉर्डरोब को क्लीन लुक देते हैं। इसमें ब्रा का ळभी सेक्शन होना चाहिए। सिंगल पैडेड ब्रा, स्पोस्टर्स, ब्रा, टीशर्ट ब्रा, रेगलुर यूज के लिए 5 से 6 अलग-अलग ब्रा रखें। आयरन की हुई शर्ट या कुर्ते हैंगर में लटकाने से अगर जगह ज्यादा घिरती है, तो उसके लिए शर्ट ऑर्गनाइजर अच्छा रहेगा।
- होम स्ट्रेप हैगिंग ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर वॉर्डरोब के अंदर की ओर किसी हुक पर लगाएं। इस पर अपनी चंकी ज्वेलरी, ब्रेसलेट, नेक पीस जैसी चीजें टांग सकती हैं, जिससे जरूरत के समय सामने नजर आए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विपक्ष के आरोपों का चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब

नईदिल्ली। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों की चुनाव आयोग की घोषणा से पहले विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि जनता ने मतदान में भाग लेकर सवालों का जवाब दे दिया है। कुमार ने कहा कि जनता मतदान में भाग लेकर सवालों का जवाब देती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, वे 100 फीसदी फुलप्रुफ हैं। अगर वे आज फिर सवाल उठाएंगे तो हम उन्हें फिर से बताएंगे। इससे पहले, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इजरायल द्वारा आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के पेजर्स को हैक करने का उदाहरण देते हुए दावा किया था कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष को इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। अन्यथा, महाराष्ट्र में, भाजपा सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती हैं।

विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

नईदिल्ली। कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की आज की बैठक के दौरान संसदीय आचार संहिता के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया। पत्र में लिखा गया है कि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल द्वारा समिति की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण ढंग से संचालित की गयी। अध्यक्ष द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनवर मनिप्पाडी को दिया गया निमंत्रण समिति के दायरे में नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि हम इस मामले में आपसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप समिति के अध्यक्ष को द्विदलीय होने और संसदीय मानदंडों को बनाए रखने के उनके कर्तव्य की याद दिलाएंगे। इससे पहले विपक्ष के कई सांसदों ने मंगलवार को वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से बहिर्गमन किया।

चाहे 84 का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा रुकेगा नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में महायुति को टक्कर देने के लिए महाविकास अघाड़ी ने कमर कस ली है। खासकर राज्य के अनुभवी नेताओं ने आगे आकर अपने दलों की कमान संभाल ली है। इनमें सबसे आगे राकांपा-एससीपी के नेता शरद पवार का नाम है, जिन्होंने अपनी उम्र और राजनीति को लेकर अहम बयान दिया है। दरअसल, हाल ही में जब शरद पवार चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ युवाओं ने उनके सामने एक बोर्ड का प्रदर्शन किया, जिसमें पवार की उम्र को लेकर तंज कसा गया था। इसमें लिखा था- 84 साल पुराना। वृद्धावस्था को लेकर इस कटाक्ष पर शरद पवार ने यह बात कही। शरद पवार ने उस पोस्टर को लेकर ही अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें। हमें बहुत दूर तक जाना है। ये बूढ़ा आदमी रुकेगा नहीं। चाहे 84 वर्ष का हो जाऊं या 90 का। ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा, जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं पहुंचा देता।

सोरेन राजवंश के आखिरी राजकुमार होंगे हेमंत : भाजपा

नईदिल्ली। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के संबंध में आज चुनाव आयोग की घोषणा से पहले, भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने शासन में कुशासन, भ्रष्टाचार, कुशासन का हवाला देते हुए सत्तारूढ़ झामुमो पार्टी पर हमला किया और दावा किया कि झामुमो को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के बाद सोरेन राजवंश के आखिरी राजकुमार होंगे। बीजेपी नेता प्रतुल शाह देव ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि यहां चुनाव होने वाले थे और विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा था, इसलिए चुनाव उससे पहले कराने पड़े। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना घबरा गया है कि उसने आधिकारिक तौर पर पोस्ट किया गया कि यह लोकतंत्र की हत्या है और वे समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका कुशासन, भ्रष्टाचार, कुशासन और लूट का राज खत्म होने वाला है और भाजपा को अपार सफलता मिल रही है। यह साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन, सोरेन राजवंश के आखिरी युवराज साबित होंगे और झामुमो को हार का सामना करना पड़ेगा।

पहलवान की ताकत अखाड़े में ही दिखती है: जीतन राम मांझी

पटना। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में आगामी उपचुनाव लड़ने के फैसले पर जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने प्रशांत किशोर के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि पहलवान की ताकत अखाड़े में ही उजागर होती है। आइये देखते हैं प्रशांत किशोर कैसे पहलवान हैं। जन सुराज को लोगों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जनता को फैसला करने दीजिए। पहले लोकसभा के लिए चुने गए मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के बाद इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव नवंबर में होंगे। जन सुराज ने चारों सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मांझी ने चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव में हर कोई अपना उम्मीदवार खड़ा करता है और कई स्वतंत्र उम्मीदवार भी होते हैं। मांझी ने कहा कि उपयुक्त उम्मीदवार चुनना लोगों पर निर्भर है। यह लोकतंत्र है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है।

विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा मे नरेंद्र मोदी बोले- 6जी पर भी तेजी से काम कर रहे

दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में भारत : प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन पीएम मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने मानकों पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को संघर्षों से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रुट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रुट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है – दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। ऐसे में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस की ये साझेदारी भी एक प्रेरक और शानदार संदेश है। पीएम ने कहा आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत में जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हैं, 95 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जहां दुनिया के 40% से अधिक वास्तविक समय में डिजिटल ट्रांसेक्शन होते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में भारत में केवल दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं और आज 200 से अधिक हैं। पहले हम ज्यादातर फोन विदेशों से आयात करते थे, आज हम भारत में पहले की तुलना में 6 गुना अधिक मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं। हम एक मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाने जाते हैं और हम यहीं नहीं रुके हैं, अब हम दुनिया को चिप्स से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी तरह से मेड-इन-इंडिया फोन उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर में भी भारी निवेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का एक साथ होना भी महत्वपूर्ण हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का लक्ष्य गोबल स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। वही इंडिया मोबाइल क़ांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। आज भारत में गुणवत्ता सर्विसेज बहुत ज्यादा फोकस कर रहे है। हम मानक पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं।

वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोलते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी साधन बनाया है। उन्होंने कहा

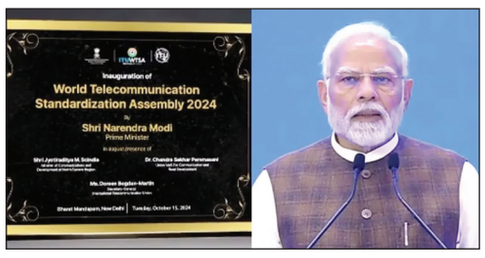

कि भारत का डिजिटल विजन चार स्तंभों पर काम करता है- सस्ते उपकरण, सभी कोनों तक कनेक्टिविटी, किफायती डेटा और डिजिटल-फर्स्ट। भारत ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 8 गुना अधिक ऑप्टिक फाइबर बिछाया है। पीएम मोदी ने कहा, तेजी से रोलआउट के बाद, भारत 6जी पर काम करते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी टेलीकॉम बाजार बन गया है। भारत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सफल निर्माण में अपने अनुभव को बाकी दुनिया के साथ साझा करेगा।

पीएम मोदी ने कहा विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वैश्विक मानकों और गुणवत्ता सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए अध्यन का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अवसर का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रजातंत्रीय किया है। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं और इन प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जन धन, आधार और मोबाइल की जेएएम ट्रिनिटी कितने ही नए नवाचार का आधार बनी है। यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं।

आठ साल में 2जी से 5जी के दौर में, 6जी में और बेहतर होंगे: आकाश अंबानी

नए भारत में, मोदी के भारत में, अब पहले की तरह काम नहीं होता। 1.45 अरब भारतीयों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय सेवाएं देने के उद्देश्य से सरकार और उद्योग के बीच एक असामान्य तालमेल है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने ये बातें वर्ल्ड टेलीकम्यूनिकेशन स्टैन्डर्डाइजेशन असेंबली में कही। आकाश अंबानी ने कहा, युवा भारत के प्रतिनिधि के रूप में, मैं युवाओं के साथ आपके अविश्वसनीय जुड़ाव और असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आकाश अंबानी ने इस दौरान हिंदी में कहा, मोदी है तो मुमकिन है... आकाश अंबानी ने विदेशी अतिथियों के लिए यह बात अंग्रेजी में भी दोहराई। आकाश अंबानी ने कहा, दुनिया उस देश से हैरान है जो आठ साल पहले 2जी की गति से रेंग रहा था और अब 5जी की गति से आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 6जी में भारत का रिकॉर्ड और भी बेहतर होगा। आकाश अंबानी ने कहा कि यूपीआई दुनिया की नंबर वन डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गई है। आज, भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जहां मोबाइल डेटा की कम कीमतों के बावजूद सबसे तेज़ इंटरनेट है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश एम अंबानी ने मंगलवार को कहा कि भारत को अधिकतम आत्मनिर्भर प्रयासों और पूरी रणनीति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तत्काल अपनाना चाहिए। आईएमसी और आईटीयूडब्ल्यूटीएसए 2024 के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए अंबानी ने सरकार से डेटा सेंटर नीति 2020 के मसौदे को आपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया ताकि भारतीय डेटा भारत के डेटा केंद्रों में ही रहे। उन्होंने कहा, भारत में बहुभाषी डेटा उत्पादन का पैमाना और गति, जो एआई क्रांति को आगे बढ़ाएगी, तेजी से बढ़ने वाली है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह डेटा सेंटर नीति के 2020 के मसौदे को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाए। भारतीय डेटा भारत के डेटा केंद्रों में ही रहना चाहिए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।

महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव

कांग्रेस ने 14 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए?

■ अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सचिन पायलट पर दांव

नईदिल्ली। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने 14 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए और झारखंड के लिए 3 नियुक्त किए। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव सचिन पायलट पर खेला गया है। झारखंड के लिए सांसद तारिक अनवर, पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू को बनाया गया है।

कांग्रेस ने मंगलवार को अपने वरिष्ठ नेताओं तारिक अनवर और अधीर रंजन चौधरी तथा तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा सदस्य अनवर, पूर्व सांसद अधीर व विक्रमार्क मल्लू वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया।

गहलोत और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुंबई एवं कोंकण क्षेत्र, बघेल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को विदर्भ (अमरवाती एवं नागपुर) क्षेत्र तथा पायलट और तेलंगाना सरकार के मंत्री उत्तर कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तथा कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल को पश्चिम महाराष्ट्र और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन एवं तेलंगाना सरकार की मंत्री अनुसुइया सीताक्का को उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए वरिष्ठ

पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को महाराष्ट्र में चुनाव के लिए वरिष्ठ समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है।

पिछली गलतियों से बचना चाहती हैं कांग्रेस, बनाई नई रणनीति

हरियाणा और महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के माहौल के बीच, पार्टियां आगामी चुनावों के लिए गठबंधन बनाने और आंतरिक विवादों को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कमर कस रही हैं। इन राज्यों में राजनीतिक परिदृश्य पार्टियों के भीतर गुटबाजी से भरा हुआ है, जो संभावित रूप से चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन का गठन विपक्ष के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम को दर्शाता है। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी (आप) जैसी पार्टियों का प्रयास एकता को दिखाना है। महाराष्ट्र में, आंतरिक विवादों के दबाव और व्यक्तिगत सदस्यों के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के बावजूद, एमवीए गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। एकता की आवश्यकता इस मान्यता से प्रेरित है कि महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत का मुकाबला केवल एकजुट विपक्ष द्वारा ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से

बेंगलुरु। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम बेंगलुरु पहुंच चुकी है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर बुधवार से शुरू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ खत्म हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से कब्जा जमाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड पर है। पहले मुकाबले में रोहित शर्मा की सेना जीत के साथ आगाज करना चाहेगी।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला पिछले कुछ मैचों से शांत रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में फैंस को कोहली से कई उम्मीदें हैं। विराट द्वारा खेली गई पिछली आठ पारियों में महज एक अर्धशतक निकला है। वो भी उन्होंने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के काफी करीब है। 16 अक्टूबर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में विराट कोहली को 9 हजार रन पूरे करने के लिए 53 रनों की जरूरत है। अगर वह ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वह टेस्ट में 9000 रन से ज्यादा बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट से पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर कर चुके हैं। वह टेस्ट में नौ हजार रन या उससे ज्यादा रन बनाने वाले 18वें बल्लेबाज भी बन जाएंगे। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 115 मैच खेलते हुए 8947 रन बनाए हैं। इसमें 29 शतक और सात दोहरा शतक शामिल है। उन्हें नौ हजार रन का बैरियर पार करने के लिए महज 53 रन की जरूरत है। कोहली ने 30 अर्धशतक भी लगाए हैं, उनका बेस्ट स्कोर 254 है। भारत तीन मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का चुनौतीपूर्ण दौरा होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 153 अंक गिरा निफ्टी 25,057 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढाव का सिलसिला जारी है। सोमवार को तेजी के बाद शेयर बाजार में मंगलवार को फिर गिरावट दर्ज की गई। मेटल और वाहन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के चलते मार्केट में गिरावट आई है। इसके अलावा सितंबर के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े निवेशकों के अनुमान के मुताबिक़ नहीं रहे हैं। इसके कारण ब्याज दरों में जल्द कटौती की संभावनाओं को धक्का लगा है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज तेजी के साथ 82,101.86 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान 81,635 से 82,300 के बीच झूलने के बाद सेंसेक्स 0.19त्न या 152.93 अंक गिरकर 81,820.12 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ़्टी-50 भी 0.28 प्रतिशत या 70.60 अंक की गिरावट लेकर 25,057.35 के स्तर पर बंद हुआ।

धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं मुकेश अंबानी

नईदिल्ली। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी खरीद सकती है। अगर ये डील होती है तो इसके साथ ही रिलायंस की एंट्री कंटेट प्रोडक्शन में हो जाएगी। करण जौहर अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की हिस्सेदारी को बेचना चाहते है। वैल्यूएशन को लेकर कंपनियों के साथ बात भी जारी है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। सारेगामा इंडिया लिमिटेड पहले धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी खरीदना चाह रही थी। ये जानकारी बीते सप्ताह ही इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए सामने आई थी। वहीं अब ये भी चर्चा है कि धर्मा प्रोडक्शन में रिलायंस हिस्सेदारी खरीद सकती है। अब तक इस डील को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है।

आरबीआई ने एसजी फिनसर्व पर 28.30 लाख का लगाया जुर्माना

नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया था। इस कारण कंपनी पर रिजर्व बैंक ने भारी जुर्माना ठोका है। एसजी फिनसर्व का नाम पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज हुआ करता था। गौरतलब है कि आरबीआई वित्तीय संस्थाओं के नॉन कंप्लाइंस मुद्दों पर नजर रखने का काम करता है। पेनल्टी जैसे एक्शन भी बैंक द्वारा संस्थानों के खिलाफ लिए जाते है। कंपनियों और बैंकों पर ऊपर केंद्रीय बैंक की नजर हमेशा रहती है। रिजर्व बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से संबंधित खास शर्तों का पालन नहीं किया है। आरबीआई की मानें तो कंपनी ने सीओआर में शर्तों का पालन नहीं किया था।

हुंडई मोटर की भारतीय इकाई का आईपीओ खुला

नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार को भारतीय बाजार में आ गया। सार्वजनिक निर्गम 17 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। इसलिए, हुंडई मोटर इंडिया की आईपीओ सदस्यता इस सप्ताह मंगलवार से गुरुवार तक बोली लगाने के लिए खुली रहेगी। ऑटो ओईएम कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ का मूल्य बैंड रू.1865 से रू.1960 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है कि सार्वजनिक निर्गम की शुद्ध आय कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ऑटो कंपनी का लक्ष्य हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ से रू.27,870.16 करोड़ जुटाना है। दक्षिण कोरिया वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपने आईपीओ से सोमवार को एंकर निवेशकों से 8,315 करोड़ रुपये जुटा लिए।

किसान-व्यवसायी देश के विकास में अहम, संरचनात्मक सुधार बेहद जरूरी

शंकर अय्यर

पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रा की लागत और अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। हालांकि, पहली नजर में स्थितियां ब्याज दरों में कटौती का संकेत दे रही थीं।मुद्रास्फीति कम हो गई है, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक दरों में कटौती कर रहे हैं और जीडीपी वृद्धि दर रिजर्व बैंक के 7.1 प्रतिशत के पूर्वानुमान के मुकाबले 6.7 प्रतिशत पर धीमी रही। रिजर्व बैंक ने दरों में कटौती तो नहीं की, लेकिन अपने रुख को बदलकर तटस्थ कर दिया, जिससे निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती का संकेत मिलता है।

बहस पैसे की लागत और विकास की गति पर केंद्रित है। पैसे की कीमत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है ऋण तक व्यापक पहुंच। जैसा कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा है, %पैसे से ही पैसा बनता है। जब आपके पास थोड़ा होता है, तो अक्सर और अधिक पाना आसान होता है। लेकिन, उस थोड़े से पैसे को पाना मुश्किल होता है। भारत की अर्थव्यवस्था ऋण असमानता की लागत और छोटे व गरीब उधारकर्ताओं को कम ऋण देने की समस्या से त्रस्त है। मौजूदा परिदृश्य समस्याओं से भरा पड़ा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई का ही उदाहरण ले लीजिए, भारत छह करोड़ एमएसएमई का घर है, उनमें से 2.97 करोड़ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। एमएसएमई जीडीपी का 30 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन का 45 फीसदी और निर्यात का 48 फीसदी हिस्सा है, और वे करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ढेरों योजनाओं के बावजूद (जैसे कि

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसने कई एमएसएमई को बचाया और मुद्रा योजना) एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच कठिन बनी हुई है।

फरवरी, 2024 की क्रिसिल रिपोर्ट से पता चला है कि इस क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पहुंच मात्र 20 प्रतिशत है। 2022 में वित्त से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने पाया कि औपचारिक ऋण केवल 39 प्रतिशत एमएसएमई को ही छू पाया है। समिति ने यूके सिन्हा विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया, कुल मांग 37 लाख करोड़ रुपये के ऋण का अनुमान है, जबकि कुल आपूर्ति 14.5 लाख करोड़ रुपये है, जिससे 20-25 लाख करोड़ रुपये का ऋण अंतर रह जाता है। फंडिंग की कमी एमएसएमई को प्रभावित करती है और प्रौद्योगिकी उन्नयन में बाधा डालती है।

दो बीघा जमीन समेत कई फिल्मों में ऋण के लिए किसानों के संघर्ष को दर्शाया गया है। उदारीकरण के 30 साल बाद भी कृषि लाइसेंस राज के अधीन है। खेती की व्यवहार्यता कानून, विनियमन और वितरण के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। कृषि के लिए बैंक ऋण 2014-15 के 6.04 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 24.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं और किसानों को ऋण लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2023 में हुए नाबार्ड के एक अध्ययन से पता चलता है कि 58 फीसदी किसान ऋण योजनाओं के बारे में जानते थे, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड लोकप्रिय है, लेकिन मात्र 28 फीसदी किसान ही ऋण ले पाते हैं। ऋण प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें जटिल प्रक्रिया, बैंक से दूरी और दस्तावेजीकरण शामिल हैं। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की ऋण से दूरी बनी हुई है। कृषि का जीडीपी में योगदान करीब 16 फीसदी है, जबकि इसमें 46 फीसदी कार्यबल लगे हुए हैं। वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में 68 फीसदी भूस्वामियों के पास एक हेक्टेयर तक जमीन है। 2019 के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी और औसत घरेलू ऋण 74,121 रुपये। किसानों की आय में सुधार और कृषि में कार्यबल के अनुपात को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिए ऋण का विस्तार करने की जरूरत है।

रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा

25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन, 13 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि उप-निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी 25 अक्टूबर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग 28 अक्टूबर को की जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं या अपने किसी प्रस्तावक या लिखित पत्र द्वारा घोषित अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से लिखित सूचना पर अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची भी इसी दिन जारी होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

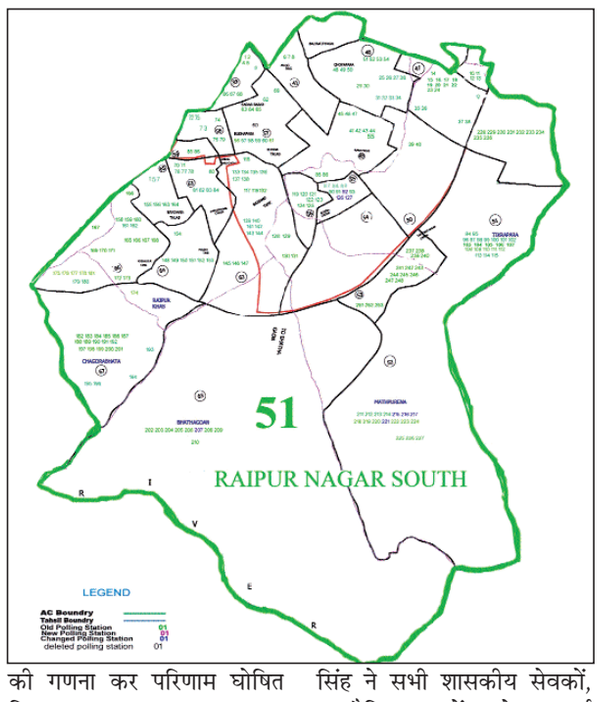

आदर्श आचरण संहिता का पालन करें- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-चुनाव की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने सभी शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शासकीय कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करें।

राजनैतिक दल तथा अभ्यर्थियों के लिए साधारण आचरण–

किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।

जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाय, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पुराने आचरण और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो, अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को उप-निर्वाचन के दौरान क्षेत्र में झण्डा खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए।

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहिए,

किसी दल द्वारा जूलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाने चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों, एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिए।

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का ऐतिहासिक मुरिया दरबार संपन्न

बस्तर दशहरा हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक-मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व हमारी आस्था और परम्परा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो सर्वाधिक लम्बी अवधि तक मनाया जाता है। बस्तर दशहरा पर्व को बस्तर अंचल के सभी लोग पूरी श्रद्धा-आस्था के साथ मनाते हैं और इसमें सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। वहीं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा अब देश-दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है, जिससे अब पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही स्थानीय लोगों की आय को संबल मिला है। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा और सभी लोगों के सहयोग से इस वर्ष भी बस्तर दशहरा का भव्य एवं सफल आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उत्काशय के उद्गार आज जगदलपुर के सिरहासार भवन में विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर आयोजित मुरिया दरबार को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने इस अवसर पर माडिया सराय में विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मांझी-चालकी और मेम्बर-मेंबरीन के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर दशहरा पर्व के ऐतिहासिक मुरिया दरबार में सम्मिलित होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि मुरिया दरबार का आयोजन सदियों से होता आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम सभी एकजुट होकर श्रद्धा और सहकार की भावना के साथ हर्षोल्लास मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित दशराहा पसरा को बस्तर दशहरा पर्व में आए मांझी-चालकी तथा अन्य लोगों को सुविधा मुहैया करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास बताया और कहा कि बस्तर दशहरा पर्व के लिए निर्धारित बजट को 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने मुरिया दरबार में मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन और बस्तर दशहरा समिति के पदाधिकारियों की मांग एवं समस्याओं को निराकृत किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा पर्व में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुरिया दरबार में बस्तर विकास प्राधिकरण के पुरखती कागजात का अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया। बस्तर दशहरा पर्व के ऐतिहासिक मुरिया दरबार में बस्तर अंचल के मंत्री, सांसद एवं विधायकों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बस्तर राज परिवार के सदस्य एवं माटी पुजारी श्री कमलचन्द्र भंजदेव, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष,बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से आये मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, ग्रामीणजन सम्मिलित हुए।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की पत्रकार वार्ता

जिला बदर बदमाश कैसे जिले में खुला घूम रहा था?

रायपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि पूरे प्रदेश के जैसे सूरजपुर जिले में लगातार आपराधिक घटनायें बढ़ गयी है। महिलायें बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक आदिवासी बच्ची को कुछ युवक अपने मोटरसाइकिल में बैठाकर ले जाते हैं दुष्कर्म की संभावना है। बच्ची को गंभीर चोटें हैं, बाएं आंख में सूजन है बच्ची के बयान अनुसार काफी मारपीट भी उसके साथ की गई। उसने बताया कि कुछ पदार्थ या तो पिलाया गया या सुंघाया गया और बेहोशी की हालत में उसको अगवा किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा था बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है एफआईआर नहीं होता है, एमएलसी नहीं होती है। सूरजपुर जिला अस्पताल से जब मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया जाता है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। परिवार बुजुर्गों से बच्ची के पिता से मैंने फोन से भी बात की और उन्हें एक ही बात कही कि हमें न्याय चाहिए। पता करने पर कि एमएलसी नहीं हो रही है बच्ची की देखरेख भी ठीक से नहीं हो रही है ऐसा सुनने में आया था। आईजी से बात किया। आईजी साहब से बात के उपरांत मुझे बताया गया कि लगभग आठ बजे के आसपास पुलिस वाले पहुंचे और शायद बयान इत्यादि लिया। बच्ची अभी भी अस्पताल में है। स्थिति स्टेबल दिख रही है बच्ची स्वस्थ हो सकती है। शेष कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर की जाएगी। बच्ची ने कुछ बयान दिए हैं लेकिन वो जांच उपरांत मेरे ख्याल से तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई धाराएं सम्पूर्ण लगेगी।

मुख्य अपराधी की गाड़ी में एनएसयूआई का नेम प्लेट इससे क्या अंदाजा लगाएं: साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर प्रवास के दौरान सूरजपुर की घटना को लेकर कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसके लिए शासन-प्रशासन है, और कानून है. इसके साथ उन्होंने कहा कि मुख्य अपराधी के गाड़ी में एनएसयूआई पदाधिकारी का नेम प्लेट लगा है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए.

भाजपा राज में बलौदाबाजार, कवर्धा अब सूरजपुर जल रहा है : डॉ महंत

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश मे लगातार घट रही आपराधिक घटनाओ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, सुशासन का राग अलापने वाली भाजपा सरकार मे लगातार घटनाओ से प्रदेश भयभीत है।छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व मे आये 24 साल हो गए कभी भी क़ानून व्यवस्था इतनी लचर नहीं रही, जितनी पिछले दस महीने मे हो गयी है। हम ही बनाएँ हैं, हम ही सँवारेंगे का यह नारा देने वाली भाजपा की सरकार से जनता पूछ रही है कि, छत्तीसगढ़ में क़ानून का राज कब सुधरेगा.

दक्षिण उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की तिथि की घोषणा का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वागत करते हुये कहा कि कांग्रेस चुनाव में जाने के लिये पूरी तरह से तैयार है। अबकी बार हम दक्षिण में नया इतिहास रचेंगे। जनता के आर्शिवाद से यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। दक्षिण विधानसभा का चुनाव में साय सरकार के 11 माह के कुशासन के खिलाफ जनता मतदान करने को तत्पर है। 11 माह में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था भाजपा की वायदाखिलाफी, सरकार का कुशासन बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। केई सरकार 11 माह के अल्प समय में ही इतनी ज्यादा अलोकप्रिय साबित हो सकती है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है। जनता भाजपा सरकार से ऊब चुकी है, अत: जनमानस भाजपा के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य की आम आदमी भाजपा के राज में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजधानी में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैण्ड में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार हो गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

विधायक साहू के परिजन साजा में आतंक का पर्याय बन गये है

रायपुर। साजा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू के द्वारा एक व्यक्ति मनीष मंडावी के ऊपर जानलेवा हमले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधायक पिता का रौब दिखाते हुये न सिर्फ गाली गलौच कर धमकाया अपने साथियों के साथ उसके ऊपर प्राण घातक हमला भी किया। युवक को गंभीर अवस्था में साजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। युवक के परिवार के लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गये थे लेकिन विधायक के दबाव में पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही है। साजा विधायक के परिजनों का आतंक बिरनपुर और चेचानमेटा में फैला हुआ है। विधायक ईश्वर साहू के परिजन साजा में आतंक का पर्याय बन गये है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सत्ता के मद में भाजपाई बेलगाम हो गये है। आम आदमी को तो भाजपाई हुक्मरान कीड़ा-मकोड़ा समझने लगे है। जब चाहे, जिसे चाहे उसके ऊपर भाजपाई हमला करते है और पुलिस उनकी संरक्षक बनी हुई है। सत्तारूढ़ दल के लोगों के संरक्षण के कारण प्रदेश में अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। भाजपाईयों के शह के कारण ही प्रदेश में अपराध

कृषि विवि में 22 से 25 अक्टूबर तक एग्री कार्नीवाल 2024

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा 22 से 25 अक्टूबर, 2024 तक चार दिवसीय एग्री कार्नीवाल - 2024 ''राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी'' का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 22 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एग्री कार्नीवाल तथा राष्ट्रीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ करेंगे। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। इस अवसर पर सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, विधायक धरसींवा अनुज शर्मा, विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोती लाल साहू एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस चार दिवसीय एग्री कार्नीवाल - 2024 ''राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी'' में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रतिनिधि, कृषि मशिनरी एवं कृषि उत्पाद निर्माता कम्पनियां, स्टार्टअप्स उद्यमी, कृषक उत्पादक संगठन, महिला स्व-सहायता समूह, विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन के कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। राष्ट्रीय किसान मेला के दौरान प्रत्येक दिन कृषकों, छात्रों एवं आम नागरिकों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्र में उगाई जा रही.

भाजपा बताये स्कूल में शिक्षक नहीं तो कैसे पढ़ेगी बेटियां

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्कूली बच्चे शिक्षकों एवं सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे है। भाजपा सरकार में शिक्षा विभाग बदहाल हो गया है। बालोद जिला के पीपरछेड़ी स्कूल के छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर शिक्षक और बिल्डिंग की मांग को लेकर आंदोलन किया, छात्रों के साथ ग्रामीण भी आंदोलन में शामिल थे। भाजपा सरकार में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भाजपा की सरकार कोई कदम उठा नहीं रही है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी निरस्त कर दी गई है, जिसके कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। स्कूल के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग है और कई जगह तो बिल्डिंग भी नहीं है। शिक्षक की कमी अलग है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री ही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बताये जब स्कूल में बिल्डिंग और शिक्षक नहीं है, तो बेटियां कैसे पढ़ेगी? भाजपा का बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ चुनावी जुमला मात्र है।

जगदलपुर-रायपुर फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

रायपुर। जगदलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर दोपहर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. यह फ्लाइट दोपहर 1 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के महज 12 मिनट बाद ही खिड़की टूटने के चलते आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी. मिली जानकारी के अनुसार, फ्लाइट के एक हिस्से की खिड़की टूटने से यह आपात स्थिति उत्पन्न हुई. पायलट ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए फ्लाइट को सुरक्षित रूप से वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया. यह लैंडिंग 1 बजकर 12 मिनट पर कराई गई. राहत की बात यह है कि फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. एयरलाइंस की टीम द्वारा तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 70 यात्री सवार थे. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब इंडिगो ने 70 यात्रियों में से कुछ को फ्लाइट टिकट के पैसे वापस किए, तो कुछ यात्रियों ने अगले दिन की फ्लाइट के लिए टिकट बुक करा लिया.

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान राज्य स्तरीय कंसलटेशन कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कंसलटेशन कार्यशाला का आयोजन राजधानी रायपुर के स्थानीय होटल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े होंगी। कार्यशाला महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को की गई थी, जिसका उद्देश्य बाल विवाह की सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को एक समन्वित रणनीति भेजी गई है। कंसलटेशन कार्यशाला का उद्देश्य विभागों के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाना और बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयासों को मजबूत करना है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दो अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए नामांकित करें और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को जागरूक करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सीएम साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जताया आभार

राजेश के प्रयास से प. विस को एक और सड़क, शुक्रवारी बाजार से स्टेशन तक 27 करोड़ से फोरलेन

रायपुर। रायपुर पश्चिम को फिर चमकाने में जुटे पूर्व मंत्री तथा दिग्गज भाजपा नेता राजेश मूणत के प्रयासों पर सीएम विष्णुदेव साय ने मुहर लगाते हुए गुढियारी को एक और फोरलेन सड़क प्रदान कर दी है। यह सड़क शुक्रवारी बाजार से शुरू होकर प्लेटफार्म-5 स्थित रेलवे फाटक को जोड़ेगी तथा पूरी तरह फोरलेन होगी। अभी यह सड़क कई जगह बेहद संकरी है। लगभग पौन किमी की इस सड़क के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 26.52 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। सड़क निर्माण की मंजूरी और फंड मंजूर करने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम विष्णुदेव साय, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर पश्चिम क्षेत्र में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए और बड़ी कोशिशें की जाएंगी। रायपुर पश्चिम के विधायक तथा तीन बार के मंत्री रहे राजेश मूणत को इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का बड़ा और मजबूत इंफ्रास्ट्र्क्चर विकसित करने के लिए माना जाता है।

रायपुर पश्चिम से गुजरनेवाली अन्य सड़कों के चौड़ीकरण तथा फ्लाईओवर्स का निर्माण मूणत के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर हुआ है। जहां तक शुक्रवारी से स्टेशन तक करीब 0.78 किमी के नए फोरलेन का सवाल है, राज्य शासन ने शासन राज्य शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि इस सड़क के निर्माण का टेंडर जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली जाए। इस सड़क पर पुल-पुलिया बनानी हो तो उसका ड्राइंग-डिजाइन भी फाइनल करवा लिया जाए। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भूअर्जन करना होगा। प्रस्ताव के अनुसार भूअर्जन की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है।

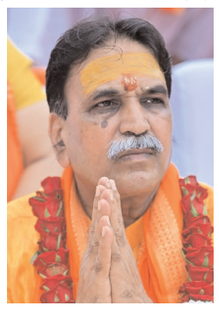

मूणत ने शासन को भेजा था इसका प्रस्ताव- पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने गुढियारी समेत समूचे रायपुर पश्चिम की फ्री तथा क्लीयर एंट्री के लिए इस सड़क का प्रस्ताव तैयार करवाया था। यह सड़क केवल स्टेशन ही नहीं, बल्कि गुढियारी को स्टेशन इलाके से जोडनेवाली महत्वपूर्ण सड़क भी है। यह कई जगह संकरी है, इसलिए ट्रैफिक में दिक्कतें होती हैं। विशेषज्ञों तथा शुक्रवारी इलाके के लोगों से लंबे विचार-विमर्श के बाद मूणत ने प्रस्ताव में सभी सुझावों को शामिल किया था। उन्होंने इस बारे में सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव से आग्रह किया था और उन्हें जानकारी दी थी कि किस तरह यह सड़क पूरे गुढियारी तथा रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश इलाके के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन की बेहद महत्वपूर्ण एंट्री हो सकती है।

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से की चर्चा

रायपुर। प्रमुख सचिव तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने गठित समिति की अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने आज मंत्रालय में विभिन्न मान्यता प्राप्त पंजीकृत अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आर चंद्रा शामिल हुए। प्रमुख सचिव श्रीमती अधिकारियों-कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा कर मांग पत्र एवं आवेदन लिया। प्रमुख सचिव

श्रीमती निहारिका बारीक सिंह ने विभिन्न स्तरों पर इनका परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रमुख सचिव और विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिए जाने और जुलाई-2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स को भविष्य निधि खाते में समायोजित किए जाने के साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के सर्वोत्तम हित में एक राज्य-एक भर्ती नियम प्रणाली लागू किए जाने, आई.ए.एस. अवार्ड हेतु एलायड सर्विसेस के अधिकारियों को एक तिहाई पदों पर अवसर प्रदान किए जाने, विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष के पदों पर विभागीय संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति कर पदस्थ किए जाने तथा शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमश: 8,16, 24 एवं 32 वर्ष में दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.